A Daily News Magazine
भोपाल
गुरुवार, 04 दिसंबर, 2025

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 94, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

एसआईआर : सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया के साथ सियासी असर भी देखे

बुरहान मजीद

सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को एसआईआर का अधिकार देने से एक ऐसी प्रक्रिया को मान्यता मिल गई है, जिसमें 'योग्यता की जांच' का नारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नए सिरे से तय करने के एक पर्दे के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर-ऊपर यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया लगती है, जिसका दावा है कि कोई पात्र वोटर न छूटे और कोई अपात्र शामिल न हो। लेकिन इस तकनीकी तर्क के पीछे राजनीतिक पहचान और नागरिकता की परिभाषा को बदल देने वाला एक बड़ा बदलाव छुपा है। जो प्रक्रिया बिहार में वोटर की पात्रता की नौकरशाही जांच के रूप में शुरू हुई थी, अब वह कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैल गई है। अगर बिहार के अनुभव से कोई सीख मिलती है, तो वह यह है कि असल में कहीं गहरे सवालों पर ध्यान देने की जरूरत है: कौन इस व्यवस्था का हिस्सा माना जाएगा? राज्य किन प्रशासनिक और कानूनी तरीकों से तय करता है कि कौन योग्य है और कौन नहीं?

इन घटनाक्रमों को समझने पर मुझे पांच प्रमुख वजहें दिखाई देती हैं, जिनकी वजह से अदालत का मौजूदा रुख न सिर्फ अपर्याप्त है, बल्कि कई मायनों में नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। पहला, एसआईआर में साबित करने की जिम्मेदारी राज्य से हटकर नागरिक पर डाल दी जाती है। पहचान से जुड़े दस्तावेजों को चुनावी सूची में शामिल होने की शर्त बना कर, एसआईआर एक ऐसी असमान परीक्षा थोप देता है, जिसे सबसे ज्यादा वही लोग झेलते हैं जो इसे पूरा करने की स्थिति में सबसे कम होते हैं। यह प्रक्रिया कुछ वोटरों को 'संदिग्ध वोटर' बना देती है–जिनकी वैधता को मान लेने के बजाय उन्हें हर बार साबित करना पड़ता है। प्रवासी मजदूर, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोग, और शहरों की योजना से अलग-थलग पड़े समुदाय–ये सभी इस उलटे पड़े संवैधानिक सिद्धांत की मार सबसे ज्यादा झेलते हैं, जैसा कि हाल की कई रिपोर्टों में सामने आया है।

दूसरा, यह बदलाव नागरिकता की मूल धारणा को ही कमजोर कर देता है और व्यक्ति को एक तरह से संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। 'योग्य' और 'अयोग्य' वोटर की सख्त संविधान ने हर वयस्क नागरिक के मताधिकार को एक स्वाभाविक अधिकार माना था, पर अब इसे एक शर्त आधारित जांच प्रक्रिया में बदल दिया गया है। इसमें ऐसे कागज मांगे जाते हैं जो सिर्फ पहचान साबित करने से आगे की बात हैं। इस तरह यह प्रक्रिया एक तरह के पर्दे के पीछे चलने वाले NRC जैसी महसूस होती है, जिसमें कागज की मांग बढ़ाकर कुछ खास समुदायों पर ज्यादा भार डाल दिया जाता है और प्रशासनिक जांच धीरे-धीरे राजनीतिक वर्गीकरण का साधन बन जाती है। एसआईआर का ढांचा असम में हुए एनआरसी जैसा लगता है, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। जिस तरह NRC ने 'असली' और 'संदिग्ध' नागरिक की श्रेणियां बनाईं, उसी तरह SIR वोटरों को 'योग्य' और 'अयोग्य' की श्रेणी में बांट देता है। तीसरा, SIR का समय इसके राजनीतिक असर को और ज्यादा बढ़ा देता है। बिहार में यह प्रक्रिया ठीक चुनाव से पहले शुरू की गई थी, जिससे यह साफ होता है कि सूची में बदलाव को राजनीतिक रणनीति की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिहार में एसआईआर के तहत हटाए गए नामो की संख्या और उनका पैटर्न देख कर कई जानकारों और विपक्षी दलों ने गंभीर चिंता जताई है। कई सीटों पर हटाए गए वोटरों की संख्या हाल में हुए विधानसभा चुनाव के जीत-हार के अंतर से भी ज्यादा है। प्रशासनिक सफाई बताई गई यह प्रक्रिया असल में चुनावी प्रतिनिधित्व में एक बड़े फेरबदल की तरह काम करती दिखाई देती है। यह भी संयोग नहीं है कि एसआईआर उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ा दी गई है, जहां चुनाव होने वाले हैं। चौथा, अदालत ने कुछ छोटे सुरक्षा उपाय जोड़े हैं, लेकिन वे केवल प्रक्रिया से जुड़े हैं, संरचनात्मक स्तर पर कोई बदलाव नहीं करते।

बिहार वाले मामले में अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि आधार को एक अतिरिक्त पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए और जिला तथा बूथ स्तर पर हटाए गए नामो की सूची सार्वजनिक की जाए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आधार नागरिकता या वोटर बनने की योग्यता साबित नहीं करता। यानि अदालत केवल प्रक्रिया के किनारे थोड़ा बदलाव करती है, लेकिन इस गहरे सवाल को छूती ही नहीं कि आखिर जांच का दबाव किन लोगों पर डाला जा रहा है और क्यों? पांचवां, जो काम केवल मतदाता सूची की एक सामान्य समीक्षा होना चाहिए था, वह अब मतदाताओं को नियंत्रित करने की एक सरकारी कवायद बन गया है।

बिहार में छह महीने पहले ही एक संक्षिप्त समीक्षा हो चुकी थी, फिर भी SIR ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू किया ताकि गहन जांच की जा सके। जो तकनीकी या नौकरशाही हस्तक्षेप लगता है, वह वास्तव में मतदान करने वालों को वर्गीकृत करने की एक राजनीतिक तकनीक के रूप में काम करता है। यह उस औपनिवेशिक शासन की याद दिलाता है, जब जनगणना, सर्वेक्षण और पहचान प्रक्रियाओं का इस्तेमाल जाति, नस्ल, जनजाति और धर्म जैसी बनाए गई श्रेणियों को स्थापित करने के लिए किया जाता था। SIR के जरिए वही तर्क फिर सामने आता है: वोटरों को 'योग्य' और 'अयोग्य' में, 'अंदर' के और 'बाहर' के लोगों में, 'नागरिक' और 'संदिग्ध' लोगों में बांटना।

इस प्रकार, जब न्यायिक जांच केवल यह देखती है कि चुनाव आयोग ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया या नहीं, तो यह उसी प्रक्रिया के गहरे राजनीतिक असर को नजरअंदाज कर देती है। मताधिकार से वंचित करना हमेशा खुले तौर पर बहिष्कार के जरिए नहीं होता, बल्कि कभी-कभी तटस्थ लगने वाले प्रशासनिक मानदंडों के माध्यम से भी होता है।

हालांकि SIR चुनावी नियमों के तहत तकनीकी रूप से वैध हो सकता है, उसकी कार्यप्रणाली औपनिवेशिक शासन जैसी लगती है, जहां जाहिर तौर पर निष्पक्ष मानदंडों के पीछे राजनीतिक रूप से प्रेरित वर्गीकरण छुपा होता है। इसलिए जो संशोधित किया जा रहा है, वह केवल मतदाता सूची नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान और संबंधित अधिकारों की सीमाएं भी हैं।

सुप्रीम कोर्ट इसे मानती है या नहीं, यह केवल वर्तमान मामले के नतीजे को ही तय नहीं करेगा, बल्कि भारत में लोकतांत्रिक पहचान और उसमें शामिल होने की भावी रूपरेखा को भी प्रभावित करेगा, खासकर विभाजन के अशांत इतिहास को देखते हुए। कानूनी प्रक्रिया को यह तय करने से बचना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से बनाए गए सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को स्वाभाविक माना जाए।

(द क्विंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

गूंगे का संवाद रही हूँ
फिर भी एक विवाद रही हूँ
शब्दों के कोलाहल में भी
अनगूंजा सा नाद रही हूँ
तुमने मुझसे कहा नहीं जो
उसका ही अनुवाद रही हूँ
विश्वासों की ईंटे जिसमें
उस घर की बुनियाद रही हूँ
निश्चित परिभाषाओं का मैं
बनकर एक अपवाद रही हूँ
खुद को तुझमें जज्ब किया है
तब जाकर आबाद रही हूँ।

- सरिता जैन

बच्चों और महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाएं : मुख्यमंत्री

लाड़ली लक्ष्मी बेटियों के ड्राप आऊट पर रखें सख्त निगरानी

- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा
- स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर गतिविधियों का करें संचालन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की गतिविधियां बच्चों और महिलाओं के पोषण व स्वस्थ सर्वांगीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। अधिक से अधिक लोगों तक विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों का सुगमता पूर्वक लाभ पहुंचाने के लिए सुशासन की भावना के अनुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए गतिविधियों का संचालन किया जाए। कार्यक्रम क्रियान्वयन के अनुवीक्षण में आईटी का अधिक से अधिक उपयोग करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को बच्चों और महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य के लिए स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के लिए कौशल उन्नयन व रोजगार की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा तथा उद्योग विभाग से बेहतर समन्वय कर गतिविधियां संचालित करने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। मंत्रालय में हुई बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों और नवाचारों का प्रेजेंटेशन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगामी वर्षों की कार्य योजना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रदेश की बेटियों के उज्ज्वल भविष्य से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है।

विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियां

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पूर्णत: ऑनलाइन पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने में मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य बना।

- टेक होम राशन की एफआरएस प्रक्रिया में मध्यप्रदेश प्रथम। राष्ट्रीय स्तर पर हुई सराहना।
- स्पॉन्सरशिप योजना में 20,243 बच्चों को लाभ। प्रदेश, देश में दूसरे स्थान पर रहा।
- भवन निर्माण की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक मॉड्यूल विकसित किया गया।
- उपस्थिति के लिए 20 मीटर जियो-फेंसिंग व्यवस्था डिजिटल पारदर्शिता की मिसाल बनी।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 9.70 लाख गर्भवती महिलाओं को 512 करोड़ रूपए से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई।
- लाड़ली बहना योजना में जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक 36 हजार 778 करोड़ रूपए का अंतरण कि किया गया।
- 1 लाख 72 हजार महिलाओं को महिला हेल्पलाइन से सहायता प्रदान की गई। वन स्टॉप सेन्टर्स द्वारा 52,095 महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई।
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 6,520 ड्राइविंग लाइसेंस और 8,637 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।
- आंगनवाड़ी केंद्रों का बड़े पैमाने पर उन्नयन करते हुए 12 हजार 670 केंद्र 'सक्षम आंगनवाड़ी' घोषित किए गए।

छत्तीसगढ़ में 12 नक्सली ढेर, 3 जवान भी शहीद

- मोदी-शाह की स्ट्रैटजी के चौथे दिन बड़ा एनकाउंटर
- सभी नक्सलियों के शव और हथियार किए बरामद

बीजापुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं, एनकाउंटर में डीआरजी के 3 जवान शहीद और 2 घायल हो गए हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी. ने पुष्टि की है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि एनकाउंटर में बीजापुर डीआरजी के जवान हेड कॉन्स्टेबल मोनू वडारी, रमेश सोड़ी और कॉन्स्टेबल दुकारू गोंडे शहीद हो गए। गंगालूर थाना इलाके के जंगलों में जवानों की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। वहीं नक्सलियों के मारे जाने के बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज हमारे बहादुर जवानों की बहादुरी से इतिहास लिखा जा रहा है। नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उन्होंने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। छत्तीसगढ़ में 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और एनएसए डोभाल समेत कई हस्तियां डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुईं। मीटिंग में नक्सलवाद को खत्म करने की स्ट्रैटजी पर चर्चा की गई थी।

जीआरपी का जल्लाद हेड कांस्टेबल!

- स्टेशन पर बेकसूर दिव्यांग को निर्दयता से पीटा, पैर मोड़ा-लातें मारी और चल दिया, निलंबित

उज्जैन (नप्र)। मानसिक दिव्यांग से नागदा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी हेड कांस्टेबल द्वारा जानवरों जैसा सलूक करने और बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इसकी पड़ताल की गई तो यह मध्य प्रदेश के नागदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक एक का निकला। रेलवे एसपी ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी जीआरपी आरक्षक को निलंबित कर दिया है।

जानकारी अनुसार नागदा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी का हेड कांस्टेबल मानसिंह प्लेटफॉर्म पर निकला तो एक दिव्यांग युवक सिर के नीचे बैग रखकर प्लेटफॉर्म सोते हुए नजर आया तो वह बिना बात के ही भड़क उठा। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। मानसिंह ने पहले दिव्यांग को सोते में ही झापड़ मार दिए। इसके बाद उसका पैर जो पहले से चोटिल है, उसे उठाकर बेरहमी से मोड़ते हुए घुमा दिया। दिव्यांग दर्द से बिलबिला उठा और माफी मांगने लगा।

गालियां देते हुए लातें मारी

हेड कांस्टेबल मानसिंह ने दिव्यांग का पैर पकड़कर न सिर्फ मोड़ा बल्कि बेरहमी से उसे दूसरी तरफ घुमा दिया, असहनीय दर्द से तड़पते दिव्यांग पर फिर भी तरस नहीं आया तो उसने दिव्यांग पर लाते बरसाना शुरू कर दिया। एक तो ठंड उपर से आरक्षक के लाते और जूतों की ठोकर से युवक दर्द से चीख पड़ा, लेकिन मानसिंह को उस पर जरा भी दया नहीं आई और गालियां देते हुए आगे निकल गया। दिव्यांग युवक बमुश्किल उठा, अपना बैग उठाया और लाचारी और मजबूरी में लंगड़ाते हुए आगे बढ़ गया।

ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया– रेलवे स्टेशन पर सामने दूसरी तरफ खड़ी किसी ट्रेन के एसी कोच में किसी व्यक्ति ने हेड कांस्टेबल आरक्षक को सोते व्यक्ति को मारते देखा तो उन्होंने मोबाइल से कैमरा जूम कर खिड़की के शीशे के अंदर से वीडियो बना लिया। हालांकि इसमें जीआरपी के हेड कांस्टेबल की निर्ममता और दिव्यांग से जानवरों जैसा सलूक की घटना कैद हो गई। बाद में उस व्यक्ति ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने बाद हड़कंप मच गया और इसकी सर्चिंग की गई तो यह नागदा स्टेशन का निकला। जिसमें हेड कांस्टेबल की पहचान होते ही रेलवे के एसपी ने तत्काल उसे निलंबित कर दिया।

एमपी, यूपी समेत पांच राज्यों के एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित

- 70 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, कहीं तकनीकी वजह तो कहीं क्रू की कमी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के 5 राज्यों के एयरपोर्ट में बुधवार को उड़ानें प्रभावित रहीं। इनमें मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। कहीं पर तकनीकी समस्या को वजह बताया गया तो किसी एयरपोर्ट पर

क्रू की कमी की बात सामने आई। दिल्ली में चेक इन प्रोसेस में दिक्कत आई जिसके बाद उसे मैन्युअल कर दिया गया। सबसे ज्यादा असर इंडिगो की फ्लाइट पर पड़ा। देशभर में इसकी 70 उड़ानें कैंसिल की गईं। जिसमें से 11 मध्यप्रदेश की थीं। वहीं हैदराबाद में 13, बेंगलुरु में 42 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ीं। वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने दुनियाभर में बड़ी सर्विस आउटेज की रिपोर्ट दी है। इससे एयरपोर्ट पर सर्विस पर असर पड़ा है। हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे नकार दिया। कंपनी ने कहा कि विंडोज पर कोई टेक्निकल समस्या नहीं आई।

राष्ट्रपति पुतिन देने जा रहे हैं 'न्यूक्लियर एनर्जी' का तोहफा!

- भारत यात्रा पर रूसी राष्ट्रपति करेंगे सबसे बड़ी डील, हो गया समझौता

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और रूस के बीच एक बहुत बड़ी डील होने जा रह है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत की यात्रा पर दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान ही दोनों देशों के बीच ये बड़ी डील होने जा रही है। दोनों देश पुतिन की इस यात्रा के दौरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने जा रहे हैं, जिसकी मंजूरी रूस ने दे दी है। ये डील सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में भारत और रूस के द्विपक्षीय सहयोग पर आधारित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की रोसाटॉम न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को रूसी सरकार की तरफ से संबंधित भारतीय अधिकारियों के साथ एमओयू साइन करने की मंजूरी मिल गई है। ये वही कंपनी है, जो तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में कई रिएक्टर बना रही है। भारत के मीडिया से बात करते हुए क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रोसाटॉम के एलेक्सी लिगाचेव कई प्रपोजल लेकर आएंगे, जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने में सहयोग भी शामिल है। इन्हें नई दिल्ली में होने वाली समिट बातचीत में पेश किया जाएगा। पहले की रिपोर्ट्स से पता चलता है कि रोसाटॉम ने भारत में एडवांस्ड रशियन-डिजाइन वाले रिएक्टर्स को लोकलाइज करने की तैयारी कर ली है है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति की यात्रा कई मायनों में अहम है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 27 °c

न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 04 दिसंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

बच्ची के लिए बने वरदान, पूरी रात न भौंके और न ही हिले

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के नवद्वीप शहर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां आवारा कुत्तों ने एक नवजात बच्ची की जान बचाई। दरअसल देर रात, जब एक बच्ची शौचालय के पास सड़क पर लावारिस पड़ा था, तो कुत्तों के एक झुंड ने उसे घेर लिया। वे बच्ची के आसपास खड़े रहे, जैसे उसकी रखवाली कर रहे हों। सुबह जब एक महिला वहां पहुंची, तो कुत्तों ने उसे रास्ता दिया और महिला ने बच्ची को बचाया। महिला ने बच्ची उठाया तो उनका दिल कांप उठा। उसने कहा कि जिन कुत्तों को हम अक्सर पत्थर मारकर भगाते हैं, उन्होंने वो किया जो शायद कई इंसान भी नहीं करते। उन्होंने इस बच्चे को जीवित रखा। यह घटना नवद्वीप के स्वराजपुर रेल कॉलोनी में हुई। राधा भौमिक ने बताया कि रात के अंधेरे में कोई नवजात बच्ची को शौचालय के पास

● नवजात को सड़क पर फेंक गई मां, आवारा कुत्ते बने रखवाले

छोड़ गया था। कुछ ही घंटों की यह बच्ची अकेली था, लेकिन आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। कुत्तों ने बच्ची को चारों ओर से घेर लिया और उसकी रखवाली करने लगे। वे न तो भौंक रहे थे और न ही हिल रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि बच्ची को उनकी जरूरत है। सुबह जब मैं शौचालय की ओर गई, तो मैंने कुत्तों को देखा। कुत्ते थोड़ा हट गए, जिससे मुझे बच्ची दिखाई दी। राधा ने कहा कि ये कुत्ते, जिन्हें हम अक्सर भगाते हैं, उन्होंने वो किया जो कई इंसान नहीं करते। उन्होंने बच्चे को जिंदा रखा। मैंने तुरंत बच्चे को गोद में उठाया और मदद के लिए चिल्लाई। राधा की आवाज सुनकर उनकी भतीजी-बहू प्रीति भौमिक दौड़कर आईं और बच्ची को महेशगंज अस्पताल ले गईं। वहां से डॉक्टरों ने बच्ची को कृष्णानगर सदर अस्पताल भेज दिया। डॉक्टरों ने बच्ची के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई। सिर पर जो खून था, वह जन्म के समय का लग रहा था। पुलिस का कहना है कि बच्ची को जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया गया था। पुलिस और चाइल्डलाइन के कर्मचारियों ने जांच शुरू कर दी है और बच्चे की सुरक्षा और देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति से संपर्क किया है।

वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश डीएसपी की बेटी से करेंगे शादी

● जयपुर के होटल ताज आमेर में लेंगे सात फेरे

मथुरा (एजेंसी)। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को जयपुर में शादी करेंगे। वे होटल ताज आमेर में देशभर के साधु-संतों की मौजूदगी में हरियाणा की शिप्रा के साथ सात फेरे लेंगे। 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक फेरे होंगे। इंद्रेश उपाध्याय सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। होटल ताज आमेर में दिनभर चलने वाले कार्यक्रम में देश-विदेश से प्रमुख मेहमान जयपुर पहुंचेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी, कथावाचक देवकीनंदन, बॉलीवुड सिंगर बी प्राक समेत कई प्रसिद्ध लोगों को निमंत्रण भेजा गया है।

भाजपा ने सोनिया गांधी नाम की महिला को बनाया उम्मीदवार

● पिता ने कांग्रेस नेता से प्रभावित होकर नाम रखा था

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल के मुन्नार का पंचायत चुनाव चर्चा में है। इसकी वजह है कि यहां के नल्लत्थानी वार्ड से बीजेपी की उम्मीदवार का नाम सोनिया गांधी हैं। यह नाम भले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष जैसा हो, लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। 34 साल की सोनिया गांधी मुन्नार की ही रहने वाली हैं। उनके पिता ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नाम पर बेटी का नाम रखा था। फिर बेटी की शादी भाजपा नेता से की। अब भाजपा ने सोनिया को वार्ड मेंबर का उम्मीदवार बनाया है। केरल में स्थानीय निकाय के चुनाव दो फेज में है। इसके लिए वोटिंग 9 और 11 दिसंबर को होगी। नतीजे 13 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। सोनिया का जन्म 1991 में कांग्रेस समर्थक के घर हुआ।

डिपोर्ट की गई गर्भवती महिला को वापस लाएं

● सुप्रीम आदेश, बोला-यहां कानून इंसानियत से बड़ा नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह नौ महीने की गर्भवती सुनाली खातून और उसके 8 साल के बच्चे को बांग्लादेश से वापस लाए। अदालत ने कहा कि कानून को कभी-कभी इंसानियत के आगे झुकना होता है। यह फैसला उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए परिवार को वापस भारत लाने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। सरकार सोनाली और उनके बेटे को भारत आने देगी। उन्होंने साफ किया कि यह अनुमति मानवीय आधार पर होगी। इससे नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर सरकार का रुख प्रभावित नहीं होगा। दरअसल सुनाली खातून को हिरासत में लिया गया था।

प्रदेश में सर्दी का दौर...

भोपाल-इंदौर में पारा 9 डिग्री से नीचे

● 5 दिसंबर से नया सिस्टम, उत्तरी हवा चलेगी; 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड

भोपाल (नप्र)। हिमालयी क्षेत्र में 5 दिसंबर से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव होने की संभावना है। मध्यप्रदेश में इसका असर अगले 2 दिन में यानी, 6-7 दिसंबर को देखने को मिल सकता है। बर्फीली हवा आने से इंदौर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और सागर संभाग में सबसे ज्यादा सर्दी रहेगी।

इससे पहले मंगलवार की रात में कई शहरों में तेज ठंड रही। भोपाल और इंदौर में पारा 9 डिग्री से नीचे रहा। वहीं, प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजगढ़ में 8.5 डिग्री, नौगांव में 8.6 डिग्री, कल्याणपुर-शाजापुर में 8.7 डिग्री, उमरिया में 9.3 डिग्री और रीवा में पारा 9.6 डिग्री रहा। इधर, दिन के तापमान में भी गिरावट का दौर जारी रहा। सुबह के समय ग्वालियर में घना कोहरा रहा। यहां विजिबिलिटी 500 से 1 हजार मीटर दर्ज की गई। भोपाल, दतिया में 1 हजार मीटर तक विजिबिलिटी रही। हिल स्टेशन पचमढ़ी में 22.6 डिग्री, बालाघाट के मलाजखंड में 23 डिग्री, शिवपुरी में 24 डिग्री, बैतूल में 24.2 डिग्री, नरसिंहपुर में 24.4 डिग्री, सिवनी में 24.6 डिग्री, धार में 25.3 डिग्री, रीवा में 25.5 डिग्री, छिंदवाड़ा में 25.8 डिग्री, उमरिया में 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बड़े शहरों की बात करें तो इंदौर में 25.6 डिग्री, भोपाल में 26 डिग्री, उज्जैन में 28.4 डिग्री, ग्वालियर में 28 डिग्री, जबलपुर में 26 डिग्री रहा।

नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ चुकी है सर्दी

इस बार नवंबर में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। भोपाल में लगातार 15 दिन तक शीतलहर चली। रिकॉर्ड के अनुसार, साल 1931 के बाद शीतलहर के यह सबसे ज्यादा दिन है।

इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने के बजाय सेना पर ध्यान दें रक्षा मंत्री

● भड़का विपक्ष, कांग्रेस ने जाहिर की तीखी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पब्लिक फंड मांगा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया था कि

नेहरू ने कभी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए सरकारी धन का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया था, जिसका सरदार वल्लभभाई पटेल ने कड़ा विरोध किया था। राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, उन्हें (राजनाथ सिंह) ऐसी जानकारी कहां से मिली। वह देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। वह चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्हें एक सीरियस पॉलिटिकल फिगर माना जाता है, मोदी जी जैसा नहीं। इसलिए उन्हें कम से कम यह डिग्निटी तो रखनी चाहिए कि जब भी आप ऐसे बयान दें, खासकर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में।

मासूम से रेप के बाद 4 दिन भोपाल में रहा सलमान

मिसरोद, गौतम नगर, गांधी नगर में खुलेआम घूमा; संरक्षण देने वाले तीन लोग गिरफ्तार

भोपाल (नप्र)। रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की मासूम से रेप के आरोपी सलमान हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत में सुधार हो रहा है। वहीं, रायसेन पुलिस ने सलमान को फरारी में संरक्षण देने के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों को सुरक्षा कारणों से भोपाल जेल में रखा गया है। पूछताछ में सलमान ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। घटना के बाद वह चार दिन तक भोपाल में रहा। इस दौरान उसने मिसरोद, गौतम नगर थाना क्षेत्र स्थित डीआईजी बंगला, टीला जमालपुरा के पुतलीघर और गांधी नगर में फरारी काटी। वह खुलेआम पीठे पर खड़े होकर मजदूरी तलाशता रहा। चोरी का मोबाइल बेचकर खाना खाया। उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। बुधवार को रायसेन पुलिस ने पुष्टि की कि सलमान भोपाल में रहकर खुलेआम फरारी काटता रहा।

भोपाल में मजदूरी की, चोरी का मोबाइल बेचा

जानकारी के मुताबिक, 21 नवंबर को आरोपी सलमान ने 6 साल की बच्ची से रेप किया था। वह उसे अधमरा ही जंगल में छोड़कर फरार हो गया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि दुष्कर्म के बाद उसने हाईवे की एक दुकान से सिगरेट ली थी, जहां पीड़िता के पिता ने उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन वह भाग निकला और जंगल में छिप गया।

जंगल में बनी एक झोपड़ी से उसने दो मोबाइल फोन चुराए और अपनी शर्ट बदली। इसके बाद वह हाईवे के रास्ते ट्रैक्टर से लिफ्ट लेकर गौहरगंज कोर्ट के सामने उतरा। वहां से जंगल के रास्ते हाईवे पर पहुंचा और बस में बैठकर नादरा बस स्टैंड गया। 22 नवंबर को आरोपी बस से हबीबगंज नाका पहुंचा और एक मोबाइल आरआरएल ब्रिज के नीचे नाले में फेंक दिया। इसके बाद डीआईजी बंगला होते हुए करोंद मंडी पहुंचकर एक सुनसान पुरानी बिल्डिंग में सो गया।

23 नवंबर को काम की तलाश में उसकी मुलाकात ठेकेदार जैद खान और मकान मालिक इंसाफ हुसैन से हुई। इन दोनों ने उसे संरक्षण दिया और निर्माणाधीन मकान में तीन दिन तक मजदूरी दी, जहां वह पुलिस से बचा रहा।

कूनो में तीन चीते रिलीज करेंगे सीएम डॉ. यादव

आज दौरा, कलेक्टर-एसपी ने तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया

श्योपुर (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 दिसंबर को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में तीन चीतों को खुले जंगल में छोड़ेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों का सोमवार को कलेक्टर अर्पित वर्मा और पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने हेलीपैड और चीता रिलीज प्वाइंट सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। शिवपुरी कलेक्टर रविन्द्र चौधरी और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर भी इस अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने शिवपुरी जिले के अहेरा गांव के पास बनाए जा रहे हेलीपैड का अवलोकन किया और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की।

सुरक्षा और मार्ग का जायजा लिया

जानकारी के अनुसार सीएम गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे श्योपुर पहुंचेंगे। अधिकारियों ने कूनो नेशनल पार्क के अहेरा गेट पर वन विभाग द्वारा किए गए प्रबंधों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अहेरा गेट से चीता रिलीज प्वाइंट तक के मार्ग का अवलोकन कर सुरक्षा, यातायात और अन्य तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए।

प्रबंधों की समीक्षा की- श्योपुर के कलेक्टर और एसपी ने शिवपुरी प्रशासन के साथ मिलकर रिलीज प्वाइंट पर किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। इस अवसर पर डीएफओ आर. थिरुकुराल, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एएसपी प्रवीण भूरिया सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

मुस्लिमों को मथुरा-ज्ञानवापी पर दावा छोड़ देना चाहिए

● ये हिंदुओं के लिए मक्का-मदीना जैसे, एएसआई के पूर्व अधिकारी की हिंदुओं को भी सलाह

कोझिकोड (एजेंसी)। इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पूर्व रीजनल डायरेक्टर केके मुहम्मद ने कहा है कि मुसलमानों को दो और ऐतिहासिक जगहें छोड़ देनी चाहिए जो मंदिर भी हैं। पहली- मथुरा जो भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है। दूसरी- ज्ञानवापी जो भगवान शिव से जुड़ी है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए केके मुहम्मद ने कहा कि ये जगहें मुसलमानों को हिंदू समुदाय को भव्य हिंदू मंदिर बनाने के लिए सौंप देनी चाहिए। मथुरा-काशी हिंदुओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए हैं। हालांकि उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि हिंदू समुदाय को अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के अलावा हर मस्जिद के पीछे नहीं जाना चाहिए। दोनों समुदायों के नेतृत्व को कुछ शर्तों पर सहमत होना चाहिए। केके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नॉर्थ जोन के रीजनल डायरेक्टर के तौर पर 2012 में रिटायर हो चुके हैं। वे 1976 में बीबी लाल की उस टीम का हिस्सा थे, जिसने बाबरी मस्जिद की खुदाई की थी। केके ने कहा कि आपको कम्युनिस्ट इतिहासकारों से इन सब बातों पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहले के मामले में भी इरफान हबीब जैसे कम्युनिस्ट इतिहासकारों और एएसआई के कुछ लोगों ने ही इस मुद्दे को उलझाया था। मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा राम जन्मभूमि सौंपने के लिए भी तैयार था क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की थी।

सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र द्वारा जागरूकता कार्यक्रम

भोपाल। सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र संस्था द्वारा आंगनवाड़ी 710 और 1146 गोविंदपुरा में विश्व एड्स दिवस, भोपाल गैस त्रासदी और विश्वास दिव्यांगता दिवस पर मानसिक समस्याओं पर जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र की निदेशक स्मिता कुमारी ने एड्स से बचाव, भोपाल गैस त्रासदी के कारण हुई मानसिक एवं शारीरिक क्षति, दिव्यांगता से बचाव, दिव्यांगता के लक्षणों की शीघ्र पहचान, उपचार, एवं उनके पुनर्वास पर चर्चा की। साथ गर्भवती माताओं एवं प्रसूति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि 1 दिसम्बर को विश्व एड्स जागरूकता दिवस, 2-3 दिसम्बर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस और 3 दिसम्बर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। यह तीनों समस्याओं से मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभावत पड़ता हैं। इसलिए आज विश्व दिव्यांगता दिवस पर मानसिक समस्याओं से बचाव के लिए बताया कि किस प्रकार से मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कैसे समानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए, बचाव और चिकित्सकीय देखरेख के बाद भी अगर किसी कारण किसी बच्चे में असामान्य विकास दिखे तो तत्काल थेरेपी से काफी हद तक स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल का आदेश वापस

● सियासी बवाल और विरोध के बीच सरकार ने पलटा फैसला ● केंद्र सरकार ने संसद में कहा था- इससे जासूसी संभव नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन पर संचार साथी ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन (पहले से डाउनलोड) के फैसले को वापस ले लिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि सिर्फ एक दिन में अपनी मर्जी से एप डाउनलोड करने वालों की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। संचार साथी एप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, सरकार ने मोबाइल बनाने वाली कंपनी के लिए प्री-इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। उधर केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि संचार साथी एप से जासूसी करना न तो संभव है, न ही जासूसी होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एप को लेकर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के

सवालों के जवाब पर कहा- फीडबैक के आधार पर मंत्रालय एप इंस्टॉल करने के आदेश में बदलाव करने को तैयार हैं। संचार साथी एप को लेकर पूरा विवाद 28 नवंबर को शुरू हुआ, जब दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल फोन निर्माताओं को एक आदेश जारी किया था। इसमें कंपनियों को भारत में बेचे जाने वाले सभी नए मोबाइल फोन के साथ-साथ मौजूदा हैंडसेटों में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए एप इंस्टॉल करना कंपलसरी कर दिया था। विपक्ष ने इसे नागरिकों की 'जासूसी' का प्रयास बताते हुए केंद्र सरकार पर 'तानाशाही' थोपने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो सकी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा- यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है।

बंगाल के भाजपा सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी

● कहा-विधानसभा चुनाव जीतना है, अभी से काम शुरू करें

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को तीसरा दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही से पहले संसद परिसर में पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने सांसदों से कहा कि राज्य के मौजूदा हालात को लेकर जनता से बातचीत की जरूरत है।

पीएम ने कहा- जमीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है, उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री ने सांसदों से डिटेल में प्रजेंटेशन तैयार करने, पॉलिटिकल प्लानिंग और लोगों को संगठित करने के लिए ग्राउंड वर्क पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा कि सांसद खगेन मुर्मू पर हमले जैसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से उजागर किया जाना चाहिए। ताकि वहां के लोग समझ सकें कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में किस तरह हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर मकर द्वार के सामने नए लेबर लॉ के खिलाफ प्रदर्शन किया।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कबीर यात्रा फिर विवादों में

4-5 हजार लोगों के प्रवेश की अनुमति

विभाग ने नहीं माने एनजीटी के आदेश

भोपाल (नप्र)। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित कबीर गुफा में हर साल होने वाली 'कबीर यात्रा' एक बार फिर विवादों में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी वन विभाग ने यात्रा के लिए नियम और गाइडलाइन तैयार नहीं की और 4 से 5 हजार लोगों को वाहनों से कोर एरिया में प्रवेश की अनुमति दे दी। इसके चलते यात्रा से पहले ही हजारों श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा शुरू हो गया है। यात्रा 4 दिसंबर को होना है।

बिना नियमों के अनुमति, टाइगर रिजर्व का रहवास खतरे में- फील्ड

डायरेक्टर ने वाहनों की सीमित क्षमता के चलते यात्रियों को पैदल यात्रा की अनुमति भी जारी कर दी है, जिसके कारण जंगल के कोर एरिया में बाघ, तेंदुए और अन्य वन्यजीवों का रहवास प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। वन विशेषज्ञों का कहना है कि कोर एरिया में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का प्रवेश न केवल वाइल्ड लाइफ एक्ट का उल्लंघन है, बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका भी बढ़ा देता है।

एनजीटी के आदेशों का सीधा उल्लंघन

एनजीटी ने 12 अगस्त 2025 को वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे की याचिका पर आदेश दिया था कि तीन महीने के भीतर कबीर यात्रा के लिए नियम व गाइडलाइन बनाई जाए। यात्रा में शामिल होने वालों के लिए अनुमति ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से हो और आदिवासी क्षेत्र होने के चलते त्रि-स्तरीय समिति से अनुशंसा ली जाए, लेकिन इनमें से किसी भी बिंदु का पालन नहीं हुआ।

पीसीसीएफ ने दी अनुमति- चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शुभरंजन सेन ने 25 नवंबर 2025 को 4-5 हजार लोगों को वाहनों से यात्रा की अनुमति जारी कर दी, जबकि त्रि-स्तरीय समिति की अनुशंसा भी नहीं ली गई। वहीं फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय ने भी अंतिम समय में 4 दिसंबर के लिए पैदल यात्रा की अनुमति मांगी, जिसे एक्टिविस्ट आदेशों का सीधा उल्लंघन बता रहे हैं।

अशोका गार्डन में दो पक्षों में विवाद

घर में घुसकर किया हमला, 2 घायल, हमीदिया अस्पताल में चल रहा इलाज

भोपाल (नप्र)। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में देर रात दो समुदायों के युवकों के बीच विवाद बढ़ते-बढ़ते मारपीट और हथियार चलने तक पहुंच गया। आरोप है कि एक पक्ष के कुछ युवक एक घर में घुसे और तलवार-छुरी जैसे हथियारों से हमला कर दो युवकों को घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में

भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनुराग लाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द गिरफ्तारियां होंगी। घटना के बाद हिंदू समाज से जुड़े कई संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता घायलों से मिलने हमीदिया अस्पताल पहुंचे। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा हिंदू समाज को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

287 स्कूलों की बाउंड्रीवॉल पर पीली लाइन खींची

यह सभी तंबाकू मुक्त घोषित, राजधानी की बस्तियों में हर 1 किमी पर 59 तंबाकू दुकानें

भोपाल (नप्र)। भोपाल में तंबाकू को लेकर दो तस्वीरें साथ सामने आई हैं। एक उम्मीद जगाती है, तो दूसरी चिंता बढ़ा देती है। उम्मीद इसलिए कि तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत शहर के 287 स्कूलों और 31 गांवों को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है, जबकि 400 स्कूलों के लक्ष्य की ओर काम जारी है। हजारों बच्चों को तंबाकू से दूर रखने के लिए जागरूकता, प्रतियोगिताएं, शपथ और स्कोरिंग आधारित सर्टिफिकेशन जैसी पहल की जा रही हैं।

लेकिन, इसी बीच एनआईआरईएच और एम्स भोपाल के संयुक्त अध्ययन ने एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया है। शहर के स्लम इलाकों में हर 1 किलोमीटर के दायरे में औसतन 59 तंबाकू दुकानें मौजूद हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत बिना लाइसेंस चल रही हैं और 43 प्रतिशत स्कूलों के पास हैं। यह विरोधाभास बताता है कि जहां एक ओर बच्चे तंबाकू मुक्त भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं आसपास का माहौल उनकी सेहत को गंभीर खतरे में डाल रहा है।

स्कूल में बनाए टोबैको मॉनिटर- अभियान की खास बात यह है कि हर स्कूल में एक टोबैको मॉनिटर चुना जाता है। यह मॉनिटर शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल में कोई भी छात्र तंबाकू का सेवन न करे और न ही परिसर के आसपास तंबाकू मिले। टोबैको मॉनिटर न केवल निगरानी करते हैं बल्कि अपने साथियों को भी जागरूक करते हैं। कई स्कूलों

में छात्र स्वयं प्रेरित होकर अपने दोस्तों को तंबाकू छोड़ने की सलाह देते हैं और इस अभियान को एक छात्र-आंदोलन का रूप दे रहे हैं।

100 अंकों पर मिलता है तंबाकू मुक्त सर्टिफिकेट- स्कूल को तंबाकू मुक्त घोषित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम 9 बिंदुओं पर आधारित 100 अंकों का मूल्यांकन करती है। इसमें परिसर में तंबाकू के उपयोग के कोई प्रमाण न मिलना, छात्रों और शिक्षकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, परिसर के बाहर 100 गज के दायरे में तंबाकू दुकान न होना, तंबाकू मॉनिटर नियुक्त होना, स्कूल में नो टोबैको बोर्ड लगाया जाना और पीक के धब्बे, पाउच और बीड़ी के टुकड़े न मिलना शामिल हैं। इन सभी बिंदुओं पर स्कूल स्कोरिंग पूरी करता है तभी उसे तंबाकू मुक्त विद्यालय घोषित किया जाता है। स्कूल के मूल्यांकन के बाद उसके प्रिंसिपल द्वारा स्व-घोषणा पत्र दिया जाता है कि संस्थान सीओटीपीए एक्ट की धारा 4-6बी का पालन करेगा। इसके बाद स्कूल की बाउंड्रीवॉल के आसपास पीली लाइन खींचकर उसे तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा के अनुसार अभियान में स्कूल शिक्षा विभाग का सहयोग प्रभावी है और इसका उद्देश्य केवल बच्चों को नहीं, बल्कि पूरे समाज को तंबाकू के खिलाफ एकजुट करना है।

तंबाकू की लत है संकट का कारण

- महिलाओं में चबाने वाला तंबाकू अधिक प्रचलित है।
- पुरुष धूम्रपान को प्राथमिकता देते हैं।
- तंबाकू सेवन से कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारियों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।
- वैश्विक स्तर पर हर साल 80 लाख मौतें तंबाकू के कारण होती हैं।
- परिवारों पर मानसिक और आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है।

राजधानी की बस्तियों में हर 1 किमी पर 59 तंबाकू दुकानें

जब स्कूल तंबाकू मुक्त भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उसी शहर की एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट भी है। एनआईआरईएच और एम्स भोपाल का संयुक्त अध्ययन बताता है कि स्लम क्षेत्रों के 40 प्रतिशत वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं। 31 से 44 वर्ष का युवा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है। सर्वे में शामिल 194 दुकानों में से केवल 18 प्रतिशत लाइसेंस प्राप्त थीं। 43 प्रतिशत दुकानें स्कूलों के 100 मीटर दायरे में हैं। हर 1 किमी के दायरे में औसतन 59 तंबाकू दुकानें मिलती हैं। स्लम में तंबाकू की उपलब्धता दूसरी बड़ी वजह है जिसकी वजह से लत तेजी से फैल रही है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि यह स्थिति आने वाले वर्षों में मुंह, फेफड़े और गले के कैंसर को और बढ़ा सकती है।

कोरोना खत्म महामारी के बहाने बढ़ाया विमानों का किराया

2019 में मात्र 1.63 करोड़ खर्च हुए, इस साल बढ़कर 90.7 करोड़ किराया चुकाया

विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने उठाया था सवाल

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में सरकारी विमान और हेलिकॉप्टर के किराए पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। विधानसभा में कांग्रेस के दो विधायकों प्रताप ग्रेवाल और पंकज उपाध्याय के सवाल के जवाब में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। 2021 की तुलना में विमानों का किराया 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। विधानसभा में पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा दी गई जानकारी ने सरकार के विमानन खर्च की पूरी तस्वीर उजागर कर दी।

11 महीनों में ही विमान कंपनियों को 90.7 करोड़ दिए- विधानसभा में दी गई जानकारी बताती है कि जनवरी 2021 से नवंबर 2025 के बीच विमान किराये पर 290 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि सिर्फ जनवरी से नवंबर 2025 में निजी कंपनियों को 90.7 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

सीएम मोहन के कार्यकाल में विमानों के किराए पर 143 करोड़ खर्च हुए- मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि वर्ष 2019 में विमान किराये पर खर्च जहां मात्र 1.63 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष था, वही खर्च 2025 में उछलकर 90.7 करोड़ प्रतिवर्ष हो गया। सीएम मोहन यादव के कार्यकाल में जनवरी 2024 से नवंबर 2025 के दौरान 143 करोड़ रुपये विमान किराये पर खर्च हुए।

कोविड के बहाने 2023 में किराया बढ़ाया

विधानसभा में दस्तावेज़ के अनुसार सरकार ने किराया बढ़ाने के लिए ये वजहें बताईं- कोविड के बाद पर्यटन बढ़ गया, विमानों की मांग बढ़ गई, कोविड के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं इसलिए मांग और बढ़ेगी, ईंधन और मेंटेनेंस महंगा हो गया है।

एमपी में इंडिगो की 11 से ज्यादा उड़ानें रद्द

क्रू की कमी से कई फ्लाइट कैंसिल

कंपनी ने नए नियमों को बताया कारण

भोपाल/इंदौर (नप्र)। मध्य प्रदेश में इंडिगो की 11 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल मैनेजर ने बताया कि इंडिगो में क्रू प्रॉब्लम होने की वजह से इंदौर आने-जाने वाली 4-5 फ्लाइट कैंसिल हैं। कुछ फ्लाइट लेट भी चल रही हैं। उन्होंने बताया कि क्रू मेंबर की कमी के कारण बुधवार को इंडिगो की देशभर से संचालित होने वाली 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उधर, इंडिगो ने पुष्टि करते हुए कहा- कुछ दिनों में हमें कई अनिवार्य कारणों से देरी और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा है। इनमें तकनीकी समस्याएं, हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ और परिचालन संबंधी जरूरतें शामिल हैं।

इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस सिर्फ 35 प्रतिशत- सूत्रों के मुताबिक, यह स्थिति नए (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) नियमों के दूसरे चरण के लागू होने के बाद पैदा हुई है। फ्लाइट कैंसिल-डिले होने का संकट मंगलवार से शुरू हुआ और बुधवार को पूरे देश में हालात और भी बदतर हो गए।

सिटी बस के टिकट कलेक्शन में गड़बड़ी

भोपाल में यात्री ने कंडक्टर से पूछा- टिकट क्यों नहीं दे रहे? जवाब- मशीन खराब है

भोपाल। भोपाल की सड़कों पर दौड़ने वाली सिटी बसों के टिकट कलेक्शन पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। एक यात्री ने टिकट कलेक्शन में गड़बड़ी को उजागर करते हुए वीडियो बना लिया। यात्री ने बस कंडक्टर से पूछा कि किराया ले रहे, लेकिन टिकट क्यों नहीं दे रहे? जवाब में कंडक्टर ने कहा कि मशीन खराब है। ऐसे में टिकट कलेक्शन राशि में गड़बड़ी सामने आई है। इसकी शिकायत भी निगम अधिकारियों से की गई है।

यात्री और कंडक्टर के बीच बातचीत का 47 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है। सिटी बस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कटारा की जा रही थी। तभी यात्री कंडक्टर से टिकट मांगता है, लेकिन मशीन खराब होने के बहाने टिकट नहीं दी जाती है, जबकि किराया ले लिया जाता है। इस पर सवारी ने ही वीडियो बनाया। जिसमें वो कह रहा है कि पूरी बस भरी है। कंडक्टर ने किसी को टिकट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया, यह सवाल है। सवाल पर कंडक्टर ने कहा कि मशीन ही काम नहीं कर रही है। इस पर यात्री ने शिकायत करने की बात कही। शाम तक निगम अफसरों तक शिकायत भी पहुंच गई।

दो तरह से गड़बड़ी- मशीन के जरिए टिकट नहीं दिए जाने पर दो तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है। पहली कि कंडक्टर निर्धारित से ज्यादा यात्रियों से किराया वसूले और दूसरा संबंधित बस एजेंसी को पूरी राशि नहीं दें।

ऐसे में आगे चलकर एजेंसी संचालक नुकसान का हवाला दें और नगर निगम से रियायत मांगें। इस तरह गड़बड़ी की वजह से यात्री और निगम पर आर्थिक बोझ आ रहा है।

भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बुरे हाल- बता दें कि भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बुरे हाल है। एक समय कुल 368 बसें सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन बाद में बसें बंद होने लगी और अब इनकी संख्या 60 पर आ गई। कुछ दिन पहले ही 16 नई सीएनजी बसें चलने लगी, लेकिन यह काफी नहीं है।

टिकट कलेक्शन के चलते ही बंद हो चुकी हैं बसें

डेढ़ साल पहले तक भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में सिटी बसों का संचालन बीसीएलएल के जरिए 4 एजेंसी कर रही थी। इनमें मां एसोसिएट्स, एपी मोटर्स, श्री दुर्गांबा और आई-मोबिलिटी एजेंसी शामिल हैं। ये एजेंसियां 25 रूट पर बसें चला रही थी। इनमें से सबसे पहले पिछले साल 4 जुलाई को मां एसोसिएट्स ने 149 बसों का संचालन बंद किया था। इसकी वजह इन बसों में टिकिट कलेक्शन करने वाली एजेंसी 'चलो एप' की ओर से प्रति? किमी दी जाने वाली राशि घटाने की मांग है, लेकिन डेढ़ साल बाद भी बीसीएलएल और निगम के जिम्मेदार इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए। इसके बाद अन्य एजेंसियों की बसें भी बंद होने लगी और संख्या 368 से घटकर 60 पर आ गई।

चलो ऐप विवाद के बाद बसें बंद कर दी गईं

चलो ऐप टिकट कलेक्शन एजेंसी थी, जिसे प्रति किलोमीटर राशि 33 रुपए देना था, लेकिन आमदनी 20 से 22 रुपए आ रही थी। इस राशि को कम करने की मांग उठ रही थी। बस ऑपरेटर और चलो ऐप में इस राशि को लेकर विवाद की स्थिति बनी। इसके बाद धीरे-धीरे बसें बंद कर दी गईं।

बैरसिया विस

एसआईआर डिजिटाइजेशन का काम पूरा

2.53 लाख वोटर्स के फार्म अपलोड किए, दूसरे नंबर पर हुजूर विस

भोपाल (नप्र)। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) में भोपाल की 7 में से बैरसिया विधानसभा में बुधवार दोपहर में डिजिटाइजेशन का काम 100 प्रतिशत हो गया। 1 महीने के अंदर यहां कुल 2 लाख 53 हजार 922 वोटर्स के फार्म डिजिटाइज किए गए। दूसरे नंबर पर हुजूर और तीसरे पर भोपाल उत्तर विस है।

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि बैरसिया विधानसभा में समय से पहले डिजिटाइजेशन का काम कर लिया गया। एसडीएम आशुतोष शर्मा, तहसीलदार समेत पूरी टीम इस काम में जुटी थी। वहीं, हुजूर में 88 प्रतिशत और भोपाल उत्तर में 85 प्रतिशत डिजिटाइजेशन हो चुका है। अगले 2 दिन में बाकी बची 6 विधानसभा में भी शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा कर लेंगे।

15 दिन में 7 से बढ़कर 80 प्रतिशत पहुंचे- भोपाल की सात विधानसभा सीटों में 21 लाख 25 हजार 908 वोटर हैं। इनमें से 21.10 लाख फॉर्म बांटे गए। 19 नवंबर तक की स्थिति में फॉर्म की वापसी का प्रतिशत 7.37 ही

था। वहीं, 1 दिसंबर को यह 66.5प्रतिशत पहुंच गया। पिछले 3 दिन से जिला प्रशासन खासकर तौर पर अलर्ट हुआ। इसके बाद आंकड़े में बढ़ोतरी हुई और यह 80 प्रतिशत तक पहुंच गया। नो मेपिंग का आंकड़ा 4 प्रतिशत है। इसे मिला दिया जाए तो यह 84 प्रतिशत तक पहुंच गया है। आंकड़ों के अनुसार, बैरसिया में 100प्रतिशत, भोपाल उत्तर में 85 प्रतिशत, नरेला में 73 प्रतिशत, भोपाल दक्षिण-पश्चिम में 69 प्रतिशत, भोपाल मध्य में 72.5 प्रतिशत, गोविंदपुरा में 71.2 प्रतिशत और हुजूर में 88 प्रतिशत डिजिटलाइजेशन का काम हुआ है।

करंट लगने से सातवीं कक्षा की छात्रा की मौत

भोपाल (नप्र)। भोपाल के गांधी नगर इलाके में रहने वाली सातवीं कक्षा की छात्रा की करंट लगने से मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पीएम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है।

जानकारी के मुताबिक शादमा पिता मुश्ताक खान (14) निवासी अर्जुन वार्ड 7 वीं कक्षा की छात्रा थी। मंगलवार दोपहर को स्कूल से लौटी थी। तब घर में चल चले हुए थे। पानी की मोटर चालू थी। उसकी बड़ी बहन ने पानी की मोटर का स्विच ऑफ करने को कहा। शादमा जैसे ही स्विच ऑफ करने पहुंची, उसे करंट लग गया। इससे बेसुध होकर वहीं गिर गई। परिजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर रवाना हुए। हमीदिया हॉस्पिटल में कुछ समय चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है।

कांग्रेस विधायक बोले- रीवा कलेक्टर भ्रष्ट, पैसा उनकी कमजोरी

अभय मिश्रा ने कहा- फसल बेचने वाले 58 किसानों के नाम पोर्टल से डिलीट कराए

भोपाल (नप्र)। रीवा जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को भ्रष्ट कहा है। मंगलवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक अभय मिश्रा ने कहा, हमारे यहां की कलेक्टर भ्रष्ट हैं। पैसा उनकी कमजोरी है। वो रुपया-पैसा कमाती हैं। उन्होंने आदमी पाल रखे हैं।

अभय मिश्रा ने कहा- हमारे यहां के 58 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने सरकार द्वारा विजया वेयर हाउस पर बनाए गए सरकारी खरीदी केंद्र पर अपनी फसलें बेची। जो किसान पहले खाद के लिए लाठी खाते हैं, उधार लेते हैं, मेहनत करके खेती करते हैं, उनका मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है।

उन किसानों से यह गलती हो गई कि उन्होंने विजया वेयर हाउस पर सरकारी नीति के तहत अपनी फसलें बेची। उन्हें फसल बेचने का दाम नहीं मिला।

मिश्रा बोले- कलेक्टर कई मामलों में बराबर पैसे लेती हैं

अभय मिश्रा ने आरोप लगाया कि सहकारिता के समिति प्रबंधक, वेयर हाउसिंग और नान (नागरिक आपूर्ति निगम) इनकी मिलकर उपार्जन समिति होती है। कलेक्टर इस समिति की अध्यक्ष होती हैं। हमारे यहां की कलेक्टर भ्रष्ट हैं। इसमें भी उन्होंने आदमी पाल रखे हैं।

संपादकीय

'संचार साथी': बवाल और सवाल

देश में सभी मोबाइल स्मार्ट फोनों में साइबर क्राइम रोकने के नाम पर 'संचार साथी एप' इन बिल्ट इंस्टाल करने के मोदी सरकार के आदेश पर बवाल मचना ही था। क्योंकि इसे व्यक्ति की निजता की सुरक्षा में सेंध माना जा रहा है। विपक्ष और निजता सुरक्षा के पैरोकार इस आदेश का भारी विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि सरकार संचार एप के जरिए लोगों की जासूसी करना चाहती है। विपक्ष ने तो इसे पेगासस 2 नाम भी दे दिया है। हालांकि यह आरोप आशंका से ज्यादा प्रेरित है, लेकिन इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि संसद में इस पर हुए हंगामे के बाद केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार एप अनिवार्य न होकर स्वैच्छिक है। लोग इसे चाहें तो हटा भी सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को इस पर भरोसा नहीं हो रहा। गौरतलब है कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने विगत सोमवार को देश में सभी स्मार्ट फोन निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोन में संचार साथी एप को प्री-इंस्टॉल करके रखें। स्मार्टफोन निर्माता इस बात को सुनिश्चित करें कि एप को न तो डीएक्टिवेट किया जाए और न ही इस पर किसी तरह की पाबंदियां लगें। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि संचार साथी एप का उपयोग 'मोबाइल उपकरणों में प्रयुक्त आईएमईआई की प्रामाणिकता सत्यापित करने' के लिए किया जाएगा। हालांकि इस आदेश में स्पष्ट नहीं है कि संचार एप की उन उपकरणों के आईएमईआई नंबर तक स्वतः पहुँच होगी, जिन पर इसे प्री-इंस्टॉल किया गया है या यूजर्स को स्वयं यह हार्डवेयर पहचान संख्या दर्ज करनी होगी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस क़दम की आलोचना की है। पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इन निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। जबकि इस निर्देश के बचाव में डीओटी ने कहा कि यह क़दम नागरिकों को नकली हैंडसेट ख़रीदने से बचाने और दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को समझने में मदद के लिए उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि संचार साथी ऐप, जिसे पहली बार 2023 में एक पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था। जिसका उपयोग स्कैम कॉल की रिपोर्ट दर्ज करने, यूजर्स को उनके नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड की पहचान करने और फोन चोरी होने पर उसे निष्क्रिय करने के लिए किया जाता रहा है। सरकार का दावा है कि इस एप के जरिए पहले हजारों चोरी हुए मोबाइलों को खोजा जा चुका है। यह भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएई) के डीएनडी ऐप की तरह है। इसका इस्तेमाल व्यावसायिक स्पैम को रोकने के लिए होता है। लेकिन भारत में स्मार्ट फोन बनाने वाली बड़ी कंपनी एपल ने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया है। दरअसल हर भारतीय नागरिक की निगरानी का टूल है। यह हर नागरिक की गतिविधियों और फ़ैसले पर नज़र रखेगा। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि इस एप से गोपनीयता को कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा बाहरी एप्स से है, जिससे हम वर्षों से निपट रहे हैं। हमें स्वदेशी एप्स अपनाने चाहिए। संचार साथी साइबर सिक्योरिटी टूल 17 जनवरी 2025 में मोबाइल एप के रूप में पेश किया गया। यह एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सरकार के अनुसार अगस्त 2025 तक यह एप को 50 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया गया। यह एप सीधे सरकार की टेलिकॉम सिक्योरिटी प्रणाली से जुड़ा हुआ है। बेहतर होता कि सरकार इस एप को प्री इंस्टाल कराने की बजाए जनजागृति अभियान चलाती कि सुरक्षा की खातिर लोग स्वयं इसे इंस्टाल करें तो कोई बवाल नहीं मचता।

संयमित मुलायम के विवादित अखिलेश

नजरिया

– स्वदेश कुमार
लेखक लखनऊ निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

उनके संवादों में संतुलन और सहिष्णुता की झलक साफ दिखाई देती थी। वे जनता और पार्टी के बीच संतुलित आदान-प्रदान पर भरोसा रखते थे, जिससे उनकी छवि एक अनुभवी और दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित हुई। इसके विपरीत, अखिलेश यादव के राजनीतिक व्यक्तित्व में आजकल तीव्रता और तेजी ज्यादा नजर आती है। वे सार्वजनिक मंचों पर और मीडिया के सामने अक्सर तीखे भाषण देते हैं, जो विवादित व्यवहार का रूप ले लेते हैं। उनका संवाद शैली अब ज्यादा आक्रामक हो गई है, जिसका उद्देश्य शायद अपनी पार्टी की धारणा को तेज और सक्रिय बनाए रखना है। लेकिन कई बार इसकी वजह से वे अपनी राजनीतिक प्रसार रणनीति में उलझन में दिखते हैं और आलोचना का सामना करते हैं।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजकल अपने हर बयान और प्रतिक्रिया की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। राजनीतिक हलकों में यह बात आम हो गई है कि वे अब हर मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए बेचैन नजर आते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि वे किसी भी घटना या विषय को लेकर अपनी मनगढ़त कहानियां बनाने लगते हैं, जिनका असलियत से ज्यादा राजनीतिक प्रभाव होता है। उनकी बयानबाजी में दिलचस्पी तो बहुत है, लेकिन यह भी देखा जाता है कि उनके हर शब्द के पीछे उनकी राजनीति की प्रतिबद्धता साफ झलकती है।अखिलेश यादव का राजनीतिक संवाद अब अधिकतर समाज के कमजोर तबकों दलित, पिछड़ा वर्ग और मुसलमान समुदाय को सक्रिय और प्रबल करने के इरादे से भड़का देने पर केन्द्रित हो गया है। उनकी पार्टी की परंपरा और चुनावी रणनीति के अनुसार ये समूह ही उनका मुख्य वोट बैंक रहे हैं। परंतु, कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश की इस झुकाव ने कभी-कभी सांप्रदायिक और वर्गीय तनाव को हवा दी है, जिससे सामाजिक समरसता प्रभावित होने की आशंका रहने लगी है। हाल के दिनों में समाज में यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि अखिलेश यादव को अपने पिता, मुलायम सिंह यादव से अपने राजनीतिक आचरण में कुछ बदलाव सीखना चाहिए। मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व और नेतृत्व शैली देश में काफी अलग तरह की मानी जाती है। वे अधिकतर शांत, संयमित और सोच-समझकर बोलने के पक्षधर रहे हैं। उनकी राजनैतिक सफलता का एक बड़ा कारण यही माना जाता है कि वे बिना ज्यादा शोर-शराबे के, स्थिति को भांपकर अपने कदम उठाते थे।

मूलतः, मुलायम सिंह यादव की रणनीति थी कि वह विवादों में कम उतरते, विवादित सवालों को धोरे-धोरे हल करते और अपने दृष्टिकोण को बिना बहुत ज्यादा उग्रता या विरोधाभास के प्रस्तुत करते। उनके संवादों में संतुलन और सहिष्णुता की झलक साफ दिखाई देती थी। वे जनता और पार्टी के बीच संतुलित आदान-प्रदान पर भरोसा रखते थे, जिससे उनकी छवि एक अनुभवी और दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित हुई। इसके विपरीत, अखिलेश यादव के राजनीतिक व्यक्तित्व में आजकल तीव्रता और तेजी ज्यादा नजर आती है। वे सार्वजनिक मंचों पर और मीडिया के सामने अक्सर तीखे भाषण देते हैं, जो विवादित व्यवहार का रूप ले लेते हैं। उनका संवाद शैली अब ज्यादा आक्रामक हो गई है, जिसका उद्देश्य शायद अपनी पार्टी की धारणा को तेज और सक्रिय बनाए रखना है। लेकिन कई बार इसकी वजह से वे अपनी राजनीतिक प्रसार रणनीति में उलझन में दिखते हैं और आलोचना का सामना करते हैं। वे आज की तेजी से बदलती राजनीति में अपनी छवि को लेकर बहुत संवेदनशील स्थिति में हैं। जब वे दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय को अपने भाषणों के जरिए सक्रिय करते हैं, तो इससे अपेक्षित वोट बैंक को भी मजबूत किया जाता है, परंतु इसके साथ ही सामाजिक सामंजस्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसके विपरीत, मुलायम सिंह यादव ने हमेशा बड़े पैमाने पर सामाजिक एकता पर जोर दिया और राजनीति को समरसता के माध्यम के रूप में देखा।

मुलायम सिंह यादव के राजनीति में संयम और समझदारी की प्रथा को देखकर यह कहना गलत न होगा कि अखिलेश यादव को अपने राजनीतिक सफर पर अधिक धैर्य और संतुलन अपनाने की जरूरत है। राजनीति केवल त्वरित प्रतिक्रिया देने का नाम नहीं है, बल्कि गहन सोच-समझकर सही रणनीति बनाकर आगे बढ़ने का भी काम है। मुलायम सिंह की तरह, जो बिना ज्यादा आवाज़ उठाए राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए थे, अखिलेश को भी अपनी बातों में वो गहराई और स्थिरता लानी होगी जो समृद्ध राजनीतिक नेतृत्व के लिए आवश्यक है। अखिलेश यादव की राजनीतिक यात्रा में बहुत अच्छे और उत्साहजनक क्षण आए हैं, पर यह भी सच है कि

इन दोनों राजनीतिक हस्तियों की तुलना में यह बात भी उभरकर सामने आती है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में ज्यादा दबदबा और सहूलियत से काम लिया। वे अक्सर विवादों से बचते हुए अपना काम करते रहे। उनकी भाषा में गरिमा और वज़न था, जिसका उनके समर्थक और विपक्षी दोनों सम्मान करते थे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की भाषा ज़्यादा तीव्र और भावुक है, जो कई बार राजनीतिक विरोधियों तक को लाभ पहुंचाती है। अखिलेश के कुछ समर्थक कहते हैं कि उन्हें अपनी बात और फैसले प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए ज़ोरदार और समसामयिक बयानबाजी करनी पड़ती है। वे कहते हैं कि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसे तेज वक्तव्य जरूरी होते हैं जो पार्टी को चुनावी मोर्चे पर सक्रिय बनाए रखेंगे। पर आलोचक इस तर्क से सहमत नहीं हैं और मानते हैं कि ये बयान तनाव और अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं, जिससे पार्टी की छवि कमजोर हो सकती है। मुलायम सिंह यादव ने सपा की बुनियाद को मजबूत कर इसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्थाई शक्ति बनाया। उन्होंने इसे संगठन के स्तर पर मजबूत किया और अपने आंतरिक मतभेदों को धीरे-धीरे सही तरीके से सुलझाया। वे चालाक और दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने अपना राजनीतिक माहौल समझकर निर्णय लिए। वहीं, अखिलेश यादव की भूमिका अधिकतर सार्वजनिक मंचों पर सक्रियता से जुड़ी है, जो संगठनात्मक मजबूती के लिए हमेशा मुफीद नहीं रहती।

इससे यह लगता है कि अखिलेश यादव को अपने पिता से राजनीति के आदर और संयम की सीख लेनी चाहिए। यह सीख उन्हें न केवल बयानबाजी में सुधार लाने में मदद करेगी बल्कि उनकी पार्टी को भी एक मजबूत और स्थिर स्थिति में लाएगी। राजनीति में भावुकता और तेज़बाजी कभी कभी खतरे की घंटी साबित होती है, जबकि संयमित और सोच-समझकर किया गया नेतृत्व पार्टी को लंबी अवधि का लाभ देता है। अखिलेश यादव को अपनी भाषा और कार्यशैली में संतुलन स्थापित करना होगा, जो न तो उनकी पार्टी के वोट बैंक को निराश करे और न ही समाज में विभाजन पैदा करे। अगर वे अपने राजनीतिक जन्मदाता मुलायम सिंह की तरह सोच-समझकर चलते हैं और अपने शब्दों को सौम्यता से चुनते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी राजनीति में नई जान आ सकती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि दोनों पीढ़ियों के नेताओं के बीच का ये फर्क उनके व्यक्तित्व, परिस्थिति और समय के अनुसार आया है। पर किसी भी परिस्थिति में संयम, सहिष्णुता और दूरदर्शिता वह मूल्य हैं जो राजनीति में स्थिरता और सफलता का मूल आधार होते हैं। अखिलेश यादव को चाहिए कि वे अपने पिता से इन गुणों को ग्रहण करें और पार्टी तथा समाज के लिए एक समंजस पूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाएं।

मोहन सरकार के विकास-विजन की नई रूपरेखा

मप्र का दूसरा अनुपूरक बजट

डॉ. मयंक चतुर्वेदी
लेखक हिंदुस्तान समाचार सेवा के क्षेत्रीय संपादक हैं।

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया वित्त वर्ष 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट राज्य की विकास प्राथमिकताओं और राजनीतिक दिशा दोनों का दस्तावेज कहा जा सकता है। कुल 13,476 करोड़ 94 लाख रुपए के इस अनुपूरक प्रावधान में ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, जल संसाधन, बुनियादी ढांचा और उद्योग निवेश को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के अनुसार यह बजट जनकल्याण और राज्य निर्माण की निरंतर यात्रा का विस्तार है। यह अनुपूरक बजट स्पष्ट संकेत देता दिखा है कि सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय कर चुकी है जिसमें गांव, गरीब, महिला, युवा और बुनियादी ढांचा विकासक्रम में सबसे ऊपर हैं। यह दिशा चुनावी राजनीति से इतर एक दीर्घकालिक विकास-ढाँचे की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश की तस्वीर भी पेश करती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान यह संकेत देता है कि घर सिर्फ एक सरंचना भर नहीं है, यह ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा का दृढ़ आधार है। यह आवंटन आवासहीन परिवारों को स्थायित्व प्रदान करता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति देता है क्योंकि निर्माण कार्य स्थानीय श्रम और सामग्री को सक्रिय करते हैं। पंचायत विभाग को 1,633 करोड़ रुपये का अनुदान 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप दिया गया है, जिससे ग्रामीण शासन तंत्र की मजबूती और अधोसंरचना विकास को वास्तविक धरातल पर कार्यान्वित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त करना ग्रामीण विकास की नींव को मजबूत करने वाला सबसे जरूरी कदम है।महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को 1,794 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय सहयोग प्रदान करके यह स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाना उसके विकास मॉडल का अहम हिस्सा है। लाड़ली बहना योजना ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है और यह आवंटन इस कायक्रम की निरंतरता और विस्तार का संकेत है। महिलाओं के हाथ में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक ढांचे को भी नई दिशा प्रदान करती है और यह योजना इसी परिवर्तन का आधार बनकर उभर रही है।

अनुपूरक बजट में जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं पर किए गए प्रावधान यह दिखाते हैं कि सरकार कृषि की स्थिरता और उत्पादकता को लेकर कितनी गंभीर है। नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए सरदार सरोवर डूब प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपये, बरगी नहर विस्तार योजना के लिए 200 करोड़ रुपये और इंदिरा सागर परियोजना के लिए 94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन विभाग को बांधों और संबंधित संरचनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये तथा बहुती फिल्टर संयंत्र-2 के फेज-2 के लिए 63 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

वस्तुतः यह निवेश सिंचाई क्षमता बढ़ाने, पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि भूमि की उत्पादकता को स्थिर करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की भावांतर/लेट रेट योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान यह बताता है कि सरकार किसानों की आय को बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित रखना चाहती है।शहरी क्षेत्रों के तेजी से विस्तार और सुविधाओं के बढ़ते बोझ को देखते हुए बजट में शहरी विकास को भी बड़ी प्राथमिकता दी गई है। अमृत मिशन 2.0 के लिए 150 करोड़ रुपये, मिलियन प्लस शहरों के लिए 115 करोड़ रुपये और एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान यह दर्शाता है कि सरकार शहरी जीवन को व्यवस्थित और आधुनिक बनाने के प्रयासों को तेज करना चाहती है। लोक निर्माण विभाग को भूमि अधिग्रहण के लिए 300 करोड़ रुपये दिए जाने से स्पष्ट है कि नई सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक उपयोग की बुनियादी संरचनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की बाधाओं को दूर किया जाएगा। यही नहीं, मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने और इसके लिए 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त स्वीकृति देने का निर्णय यह दर्शाता है कि शहरों में पेयजल, स्ट्रीट लाइट, नाली, खेल मैदान, सामुदायिक भवन और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास को गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,062 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें 325 पूर्ण, 407 प्रगतिरत और 330 डीपीआर या निविदा प्रक्रिया में हैं। औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े वित्तीय प्रावधान किए हैं। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को भूमि अधिग्रहण, सर्वे, डिमार्केशन और सेवा शुल्क आदि के लिए 650 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि उत्पादन संस्थाओं को ऋण सहायता हेतु 2,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत राशि का प्रावधान किया गया है। यह निवेश राज्य में नए उद्योगों को आकर्षित करने के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र को भी मजबूत करेगा जो मध्य प्रदेश में रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधि का प्रमुख आधार है। औद्योगिक आधार को मजबूत किए बिना राज्य की विकास गति को बनाए रखना संभव नहीं है और सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है।इसी तरह शिक्षा विभाग और जनजातीय विकास को भी बजट में समुचित स्थान दिया गया है। पीएम जनमन (समग्र शिक्षा) के लिए 122 करोड़ रुपये और धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नयन अभियान के लिए 108 करोड़ रुपये का प्रावधान यह दर्शाता है कि सरकार शिक्षा के साथ-साथ जनजाति क्षेत्रों के विकास को भी समान महत्व देती है। जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर किया गया निवेश राज्य के समावेशी विकास मॉडल को मजबूत बनाता है। कुल मिलाकर इस अनुपूरक बजट को लेकर यही कहा जाएगा कि मप्र में डॉ. मोहन यादव की भाजपा सरकार अपने विकास एजेंडे को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लागू कर रही है। गांवों में आवास और पंचायतों को सशक्त करने से लेकर महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, किसानों की आय सुरक्षा, जल और सिंचाई संरचनाओं का विस्तार, शहरों की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने और औद्योगिक निवेश बढ़ाने तक सरकार का हर कदम एक व्यापक और संतुलित विकास दृष्टि को सामने रखता है। कहना होगा कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का जोड़-घटाव तक सीमित नहीं है, यह तो मध्य प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देने का संकल्प है। अब यदि इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो निश्चित ही राज्य ग्रामीण समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, कृषि स्थिरता और शहरी आधुनिकीकरण के नए मुकाम हासिल कर सकता है। मोहन सरकार का यह बजट बताता है कि मध्य प्रदेश आज सिर्फ विकास की अपनी गति नहीं बढ़ाना चाहता है, वह इससे कहीं आगे विकास की दिशा भी बदलना चाहता है, जिसमें समानता, समावेशन और सतत प्रगति बराबर से समाहित हो।

हर मानव अर्जुन और गीता उसका कृष्ण

दृष्टिकोण

डॉ. मनमोहन प्रकाश
लेखक प्रोफेसर हैं।

मानव जीवन का हर चरण एक नए कुरुक्षेत्र की तरह सामने खड़ा होता है-संघर्षों, दुविधाओं और निर्णयों से भरा हुआ। परिस्थितियाँ बदलती हैं, युग बदलते हैं, साधन बदलते हैं, पर मनुष्य का मूल संकट वही रहता है- क्या सही है, क्या कर्तव्य है, क्या चुनें, कैसे चलें? यही मन की वह स्थिति है जिसमें आज का हर मनुष्य कहीं न कहीं संकोच और भ्रम से ग्रस्त, कर्तव्य और मोह के बीच डांवाडोल अर्जुन बन जाता है और ऐसे हर क्षण पर गीता उसकी कृष्ण बनकर सामने आती है, मार्ग दिखाती है, मन को स्थिर करती है, और जीवन-दर्शन के सत्य को उजागर करती है।

कुरुक्षेत्र की भूमि किसी दूर अतीत की स्मृति मात्र नहीं; वह हर उस क्षण में जीवित है जब मनुष्य अपने निर्णयों के भार से दब जाता है। अर्जुन का धनुष आज के जीवन में हर भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के हाथ में है, फिर चाहे वह विद्यार्थी हो, परिवार का सदस्य, कर्मचारी, नेता, व्यापारी ,उद्यमी, किसान या नागरिक। मोह, अपेक्षाएँ, भ्रम, दबाव और परिणामों की चिंता व्यक्ति को उसी तरह विचलित करती है जैसे अर्जुन युद्ध के द्वार पर विचलित हुआ था। ऐसे समय में गीता का यह संदेश कि कर्म मनुष्य के हाथ में है, फल नहीं,आज के अनिश्चित, प्रतियोगी और तनाव से भरे वातावरण में मानसिक संतुलन की सबसे बड़ी कुंजी है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि व्यक्ति प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करे, परिणाम पर नहीं।कर्मयोग का सिद्धांत आज के कार्यस्थल में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। आसक्ति रहित कर्म करने का विचार 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' (इमोशनल इंटेलिजेंस), 'कार्य-जीवन संतुलन' (वर्क-लाइफ बैलेंस) और 'मानसिक स्वास्थ्य' (मेंटल वेल-बीइंग) के आधुनिक सिद्धांतों से कहीं अधिक गहरा और व्यावहारिक है। गीता का यह संदेश कि मनुष्य कर्म करते समय जितना अपेक्षाओं और अहंकार से मुक्त होगा , वह उतना ही अधिक संतुलित और सफल होगा, गीता को केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन-प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ संदर्भ ग्रंथ स्थापित करती है।

कृष्ण अर्जुन से संवाद करते हुए न आदेश देते हैं, न दबाव बनाते हैं; वे तो अर्जुन की मनःस्थिति को समझते हुए उसके भ्रम का धैर्यपूर्वक समाधान करते हैं, और उसे कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के प्रभावी नेतृत्व की कसौटियाँ जैसे सहानुभूति, जागरूकता, संवाद और प्रेरणा आदि सभी आदर्श रूप में कृष्ण-अर्जुन संवाद में देखने को मिलती हैं। आधुनिक प्रबंधन में 'रूपांतरणकारी नेतृत्व' (ट्रांसफ़ॉर्मेशनल लीडरशिप) का जो सिद्धांत पढ़ाया जाता है, वह गीता के नेतृत्व दर्शन का ही आधुनिक रूप है। अविश्वसनीय लेकिन सत्य यह है कि गीता का मनोवैज्ञानिक पक्ष आज विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण, मन की स्थिरता, विचारों का अनुशासन और ध्यान का अभ्यास आधुनिक मनोचिकित्सा में संज्ञानात्मक चिकित्सापद्धति (कॉग्निटिव थेरेपी) और सचेतन ध्यान (माइंडफुलनेस) के रूप में उपयोग किए जाते हैं। 'स्थितप्रज्ञ' का आदर्श उस व्यक्ति की छवि है जो परिस्थितियों के उतार-चढ़ाव में भी संतुलित रहता है; आज की भाषा में यही धैर्य-सामर्थ्य (रेज़िलिएंस) और भावनात्मक स्थिरता (इमोशनल स्टैबिलिटी) है।गीता का धर्म संकीर्ण धार्मिकता नहीं, बल्कि कर्तव्य और नैतिकता का विज्ञान है। यह बताता है कि सही वही है जो व्यापक हित और सत्य पर आधारित हो। आज जब समाज मूल्य-संकट, भ्रष्टाचार, नैतिक भ्रम और आत्मकेंद्रित प्रवृत्तियों से जूझ रहा है, गीता का यह उपदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को पहचानकर, सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। यही संदेश अर्जुन को दिया गया था, और वही संदेश आज के मानव को चाहिए।गीता की प्रासंगिकता का वैश्विक प्रभाव और स्वीकारता इसे और भी अधिक प्रमाणिक ग्रंथ स्थापित करती है। गांधी से लेकर आइंस्टीन और ओपेनहाइमर तक, विश्व के अनेक महान विचारकों ने गीता से प्रेरणा ली। भारत सहित रूस, फ्रांस, अमेरिका तथा जापान तक में गीता पर शोध होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। हार्वर्ड, एम.आई.टी. और अन्य वैश्विक विश्वविद्यालयों में गीता को नेतृत्व, नैतिकता और मनोविज्ञान के संदर्भ में पढ़ाया जा रहा है। यह अपने आप में सिद्ध करता है कि गीता किसी विशेष समुदाय की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की ज्ञान-पुस्तक है। आज का मानव अतीत से अधिक तनाव, असंतुलन और अनिश्चितता का सामना कर रहा है। भविष्य की चिंता और अतीत का भार उसके वर्तमान को खोखला तक कर देता है। ऐसे विषम परिस्थितियों में गीता उसे यह कला सिखाती है कि वर्तमान में कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे संतुलित रखा जाए, और कैसे अपने भीतर के अर्जुन को शक्ति प्रदान की जाए। यही कारण है कि गीता आज केवल प्रासंगिक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य हो उठती है।

अंततः सत्य यही है कि जीवन के विविध मोड़ पर मनुष्य कभी न कभी अर्जुन बन जाता है (दुविधाग्रस्त, प्रश्नों से भरा, निर्णयों से विचलित) और ऐसे कठिन समय में हर बार गीता उसके सामने कृष्ण बनकर खड़ी हो जाती है (सत्य, विवेक और कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए)। यही कारण है कि गीता आज भी जीवित है, प्रासंगिक है, और मानव जीवन की सबसे स्थायी दिशा-दर्शक प्रकाश किरण है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

मूछों का नहीं अब दाढ़ी का क्रेज !

व्यंग्य

संजय तेलंग
(वरिष्ठ पत्रकार और व्यंग्यकार)

कभी मूछों को व्यक्ति की शान का प्रतीक माना जाता था। मूछों से ही किसी के व्यक्तित्व का अंदाज लगाया जाता था। बड़ी और घनी मूछ वाला अक्सर रौबदार होता था। उसके सामने कुछ भी बोलने से पहले कोई भी एक बार सोचता जरूर था। सेना में मूछ वाले अफसर के फोटो को देख ही दुश्मनों के हौंसले बिना मुकाबले पस्त हो जाते थे। वहीं पुलिस के मूछों वाले दरोगा से क्षेत्र के गुंडे थर-थर कांप उठते थे। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि आदमी की शान की प्रतीक मूछों का समय बीत चुका है।

दरअसल, अब दाढ़ी का क्रेज आ चुका है। यह क्रेज इतना सिर चढ़कर बोल रहा है कि सींकिया नौजवान भी दाढ़ी रखने लगे हैं। फिल्मों से आए दाढ़ी के फैशन ने युवाओं को इस कदर दाढ़ी का दीवाना बना दिया है कि वे स्कूल-कॉलेज तो ठीक अपनी शादी में भी शेव कर नहीं जाते। सजी-धजी दुल्हन के साथ खड़े दूल्हे को देख कोफ्त होने लगती है। भाई को अपनी शादी में ही शेव करने की फुरसत नहीं मिल सकी। क्लीन शेव की बात ही कुछ और है। क्लीन शेव वालेहमेशा आंखों को सुहाते हैं, यह हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमारी न ठीक से मूछ है और न ही दाढ़ी (जैनेटिक वजह)।

बहरहाल शादी के एक रिसेप्शन में हम दूल्हे की ऐसी ही लापरवाही पर भाषण झाड़ रहे थे, तभी पास खड़े अधेड़पन के मुहाने पर आ पहुंचे परिचित बोले-भाई साहब ऐसी बात नहीं है। युवाओं में आजकल दाढ़ी रखने का फैशन है! हमने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और फिर दूल्हे-दुल्हन पर नजर डाली। दाढ़ी वाले दूल्हे के पास खड़ी नई-नवेली दुल्हन मेकअप में लिपटी अजीब सी कोई चीज नजर आ रही थी। हर रिसेप्शन की तरह मेहमानों को खूब इंतजार करवा कर दुल्हन अभी-अभी ब्यूटी पार्लर से सीधे मंच पर पहुंची थी। उसे देख पहले तो हम पहचान ही नहीं सके, कि यह पड़ोस वाले शर्मा जी की ही बेटी है, जिसे हम उसके जन्म के बाद से ही देखते आ रहे हैं। एक बार तो लगा किसी और केरिसेप्शन में तो नहीं पहुंच गए! हमने साथ वाले से कंफर्म किया कि भैया यह शर्मा जी की बेटी का ही रिसेप्शन है ना? साथ वाले ने स्टार्टअप में मिले बड़े से पनीर के दुकड़े को हलक से उतारते हुए कहा-नो डाउट आप सही जगह पर हीहैं।

दुल्हन के चेहरे, आंखें, भोह और बालों को पार्लर बाला ने मोटी राशिलेकर इस कदर बिगाड़ा था कि वह बयाने काबिल नहीं है। शर्मा जी की सुन्दरबेटी मुन्नी (सभी उसे इसी नाम से पुकारते हैं) कोई और ही दिखाई दे रही थी। हमें तो भैया उसका नया रूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारा चेहराभांपते हुए पहले वाले रिश्तेदार फिर बोले-आजकल दुल्हनों को इसी तरह सजायाजाता है। दुल्हनें ऐसी ही अच्छी लगती हैं। यह उनका रिसेप्शनों में जातेरहने का अनुभव बोल रहा था और हमारे जैसे रिसेप्शन से बचने वाले अनाड़ी के अज्ञानी होने का प्रमाण भी था। वे फिर फूटे-आपने दूल्हे को नहीं देखाकितना खुश दिख रहा है दुल्हन को देखकर। दुल्हन को भी देख लो दाढ़ी वाले दूल्हे को देख फूली नहीं समा रही है। उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ दिया कि दूल्हा भी सेलून से ही आया है। अपने बाल और दाढ़ी ट्रिम करवा के।

नए जमाने के दूल्हा-दुल्हन को देख हमें पुराना दौर याद हो आया। दूल्हा-दुल्हन को वैवाहिक रस्म के तहत पहले हल्दी लगाई जाती थी। विवाह वाले दिन उन्हें हल्दी-चंदन के उबटन से स्नान करवाया जाता था। इससे दोनों का रूप बिना ब्यूटी पार्लर या सैलून जाए ही निखर उठता था। विवाह से पहले दूल्हे के बालों को नाई संवारता था, और शेविंग करते समय चेहरे पर बाल का एक भी खूंटा नहीं रहने देता था। दूल्हा जब सज-धज कर घोड़ी पर सवार होता था तो लोग उसकी खूबसूरती देख कर निहाल हो उठते थे। घर की बड़ी महिलाएं उसके चेहरे पर न दिखने वाला काला टीका लगा दिया करती थीं ताकि नजर न लग जाए। नए जमाने की बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन एक विचार जरूर मन में आया कि जो ब्यूटी को बिगाड़े उसे ब्यूटी पार्लर की जगह भूतनी पार्लर क्यों न नाम दे दिया जाए।

अच्छे दिनों की याद में खोए थे, तभी डीजे की धमक से ध्यान भंग हुआ। डीजे पर बज रहे तेज संगीत से दिल धक-धक करने लगा, लगा उससे दूर नहीं गए तो कहीं दिल सीने से निकल कर कहीं नीचे न जा गिरे। नए जमाने के एक गीत पर छोरे-छोरी तो कमर थिरका ही रहे थे, बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं को भी थोड़ी ना-नुकुर के बाद उन्होंने नृत्य के लिए मना लिया था। वे भी बच्चों की खुशी में खुश, वाले अंदाज में हाथ ऊपर-नीचे कर नृत्य की नाकाम कोशिश करने में लग गए। मौके पर परफ्यूम के साथ एक और गंध भी हवा में तैर रही थी। दोनों गंध मिलकर अजीब सी दुर्गन्ध का अहसास करवा रहे थे। हम भी स्टार्टर समाप्त कर खाने की मेजों की तरफ कूच कर गए, क्योंकि वहां से अपनी पेट-पूजा के लिए प्लेट में कुछ जुटा पाना आसान नहीं था, क्योंकि भीड़ टूटी पड़ रही थी!

मुद्दा

आरबी त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

ऐसे ही बनेगा भोपाल स्मार्ट सिटी ?

भोपाल बड़ा शहर है, प्रदेश की राजधानी है। यहां हो रहे विकास- निर्माण कार्यों से धूल, वायु, शोरगुल, वाहनों के धुंए, हार्न से प्रदूषण नहीं होगा तो क्या किसी जंगल में होगा। आपको वायु, ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत पेश आ रही है तो शहर से कहीं दूर रहने चले जाइये। यह जवाब या सफाई भोपाल में चल रहे गहरी सीवर लाइन तथा व्हाइट टॉप तकनीक से बन रही सड़कों के निर्माण से जुड़े कारकून का हो सकता है। बेफिक्र और निर्भीक होकर वे अपने उदगार व्यक्त करते हैं। शायद उनका इस बात से कोई वास्ता नहीं कि रहवासियों, वाहन चालकों और राहगीरों को इसके चलते कितनी मुसीबत उठाना पड़ती है।

अब आप कौन होते हैं यह सवाल करने वाले कि सड़क बनाने यह ऐसी कैसी अनोखी तकनीक है कि लोगों के घर और मेन गेट, प्रतिष्ठान नीचे चले गये और सड़कें ऊपर। इसका असली दुष्परिणाम बारिश में आयेगा जब घरों में पानी घुसेगा। कभी भी रात-बिरात, दिनदहाड़े लोगों को बताये बगैर किसी भी रहवासी इलाके में जेसीबी/बुलडोजर सड़क के बीचों-बीच नालीनुमा गड्ढे खोदकर मिट्टी गिट्टी रेत के ढेर लगा जाते हैं। इन पर से गुजरने वाले खासकर दुपहिया वाहन चालक फिसलें, गिरे- पड़ें, चोटिल हो जायें, जिम्मेदारों की बला से। मजे की बात यह है कि जल भराव और सीवेज की समस्या के स्थाई हल के उद्देश्य से यह सब चल रहा है।

सो, पॉश कही जाने वाली अरेरा कॉलोनी, व्यस्ततम 10 नंबर मार्केट, वंदे मातरम चौराहे से दस नंबर, राजीव गांधी चौराहा तथा भोजपुर क्लब की ओर जाने वाली सड़कों, ई 7 तथा अरेरा कॉलोनी के अन्य इलाकों में धूम (धूल, प्रदूषण) मचाने के बाद अब गुलमोहर कॉलोनी की अंदरूनी सड़कों पर यही सब दृश्य देखे जा सकते हैं। आप यदि दुपहिया वाहन पर चल रहे हैं तो सोच-समझकर, संभलकर इन इलाकों से गुजरिये क्योंकि कब कहाँ आपका सामना गड्ढों, मिट्टी गिट्टी, रेत के ढेर से हो जाये कहना मुश्किल है। हमने स्वयं अनुभव किया है कि मेन रोड की भीड़भाड़, बेतरतीब ट्रेफिक से बचने के लिये अंदरूनी रास्तों का इस्तेमाल भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है। गुलमोहर कॉलोनी सहित कई सड़कों पर वाहन चालकों के लिये किसी तरह के संकेतक नहीं लगाये गये हैं। बीते दिनों मुझे अपने मित्र के साथ 80 फुट रोड से नहर के समीप के चौराहे से निकलने में तीस मिनट से ज्यादा वक्त जाया करना पड़ा था। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि जाम को देखते हुए मुझे मित्र की कार से उतरकर पैदल ही त्रिलंगा आना पड़ा जबकि वह समय दोपहर का था।

उधर शाम के समय पीक ऑवर में बिट्टन मार्केट या राजीव गाँधी चौराहे से गुजरना बहुत तकलीफ़देह होता है। अधिकांश समय ट्राफिक लाइट बंद होने पर वहाँ मौजूद पुलिस कर्मियों की कोई सुनता नहीं और लोग मनमाने ढंग से वाहन निकालते हैं। इससे नियमों का पालन करने वाले ताकते रह जाते हैं। खासकर नौसिखिये वाहन चालकों को ना तो चालान कटने का भय और ना ही दुर्घटना का। दुपहिया वाहन पर चलने वालों के लिये अब पीछे बैठने वालों को भी हेल्मेट अनिवार्य है लेकिन चालक स्वयं हेल्मेट धारण कर लें यही गनीमत है। यानी यह नियम शुरूआत में ही दम तोड़ता नजर आता है। कार चालक भी शीटबेल्ट बांध लें तो उनकी हिफाज़त समझ लीजिये अन्यथा आये दिन की दुर्घटनाएं कुछ ओर ही इशारा करती है।

सो, पॉश कही जाने वाली अरेरा कॉलोनी, व्यस्ततम 10 नंबर मार्केट, वंदे मातरम चौराहे से दस नंबर, राजीव गांधी चौराहा तथा भोजपुर क्लब की ओर जाने वाली सड़कों , ई 7 तथा अरेरा कॉलोनी के अन्य इलाकों में धूम (धूल, प्रदूषण) मचाने के बाद अब गुलमोहर कॉलोनी की अंदरूनी सड़कों पर यही सब दृश्य देखे जा सकते हैं।

हालांकि पुलिस ने भी डाल डाल पांत पांत को अपनाकर चालान काटने के नये ठिये ढूंढ लिये हैं। उन्होंने अपेक्षाकृत कम ट्राफिक और सुनसान रास्तों को इसके लिये चुन लिया है।

दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की खबरें जब तब सुर्खियों में बनी रहती है तो भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में भी प्रदूषण के हालात सामान्य नहीं है। इसके पीछे की प्रमुख वजहों में बढ़ते अनियंत्रित यातायात, मौसम, होटल रेस्टोरेंट से होने वाले शोरगुल और अब शादी-ब्याह के सीजन में डीजे का कानफाडू शोर शामिल है। अकेले गुलमोहर से सटे सहकारी परिसर, सहकार नगर, आकाश गंगा, त्रिलंगा में मुख्य सड़क के साथ रहवासी मकानों के आसपास खुलेआम होटलें रेस्टोरेंट चल रहे हैं। इनसे रहवासियों को होने वाली परेशानियों का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। दो उदाहरण ही पर्याप्त हैं- शोरगुल से तंग आकर ख्यात विचारक और लेखक अनिल सदगोपाल तथा एक पूर्व डीजीपी यहां का अपना घर छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं। यहाँ खासकर सीनियर सिटीजन के लिये यह सब परेशानी का सबब बन गया है।

त्रिलंगा तिराहे से एक मॉल की ओर जाने वाली रोड पर ट्राफिक का दबाव इस कदर बढ़ गया है कि रोड क्रास करना खतरे से खाली नहीं है। दुकानों/ प्रतिष्ठानों के के सामने बड़ी लग्जरी गाड़ियां बेतरतीब तरीके से खड़ी कर दी जाती है। उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। रहवासी इलाकों में घरों के सामने कारें खड़ी करना फैशन में शुमार हो गया है। छोटे रहवासी मकान तो छोड़िये बड़े भवनों में भी पार्किंग स्पेस नहीं रखने से वाहन सड़कों की शोभा बढ़ाते दिखते हैं।

सो, कुल मिलाकर लब्बोलुआब यह है कि कितनी भी बड़ी बड़ी बातें की जायें, स्मार्ट सिटी, मेट्रो ट्रेन से लोगों को लुभाया जाये हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जिम्मेदार पल्ला झाड़कर एक दूसरे पर जिम्मेदारी का भार डालते हैं और ढांक के तीन पांत की तरह सब कुछ....ऐसे ही चलता रहता है, आगे भी चलता रहेगा।

अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस

अरूण कुमार डनायक

लेखक स्टेट बैंक के सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी हैं।

नवाचार, समावेशन और बैंकिंग का बदलता भारत

भारत में वित्तीय समावेशन की आधारशिला आज़ादी के बाद ही रखी गई थी। 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का गठन, अगले दशक में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, लीड बैंक योजना जैसे निर्णायक कदमों ने बैंकिंग को ग्रामीण भारत तक पहुँचाया। बैंक शाखा विस्तार नीति, स्वयं-सहायता समूह और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के प्रसार ने वंचित वर्गों को औपचारिक वित्त से जोड़ा। 2005-06 में 'वित्तीय समावेशन' शब्द के औपचारिक प्रयोग के साथ ही 'नो-फिल्स खाता' शुरू हुआ, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री जनधन खाते का आधार बना। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद से सरकारों और बैंकों के सतत प्रयासों ने वित्तीय समावेशन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस घोषित किया है। यह दिवस बहुपक्षीय विकास बैंकों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है, जिसके माध्यम से वे सतत विकास लक्ष्यों (2030) की प्राप्ति, सदस्य देशों में जीवन स्तर सुधार और वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करते हैं। 2020 से मनाया जा रहा यह दिवस याद दिलाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और आर्थिक अवसरों जैसे सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में बैंकिंग प्रणाली ही वित्तीय संसाधन और समावेशन की मूल आधारशिला है। कई देशों ने वित्तीय समावेशन को गरीबी उन्मूलन का प्रभावी साधन बनाया है।बांग्लादेश ने माइक्रोक्रेडिट मॉडल से लाखों गरीब परिवारों, खासकरमहिलाओं की आय बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता पाई। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक के इस योगदान को 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केन्या ने मोबाइल मनी के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की बचत, आय और आपदा-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया। रवांडा, फिलीपींस, इंडोनेशिया और पेरू ने डिजिटल बैंकिंग, समूह-आधारित ऋण और फिनटेक नवाचारके जरिए बड़ी आबादी को औपचारिक वित्त से जोड़ा। इन देशों का अनुभव दिखाता है कि जब वित्तीय पहुँच आसान होती है, तो गरीब परिवार अधिक स्थिर, आत्मनिर्भर और अवसर-संपन्न बनते हैं।

भारत में वित्तीय समावेशन की आधारशिला आज़ादी के बाद ही रखी गई थी। 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का गठन, अगले दशक में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, लीड बैंक योजना जैसे निर्णायक कदमों नेबैंकिंग को ग्रामीण भारत तक पहुँचाया। बैंक शाखा विस्तार नीति,स्वयं-सहायता समूह और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के प्रसार ने वंचित वर्गों को औपचारिक वित्त से जोड़ा। 2005-06 में 'वित्तीय समावेशन' शब्द केऔपचारिक प्रयोग के साथ ही 'नो-फिल्स खाता' शुरू हुआ, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री जनधन खाते का आधार बना। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद से सरकारों और बैंकों के सतत प्रयासों ने वित्तीय समावेशन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया।

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य कमजोर वर्गों को किफायती और समय पर वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना है। आज प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण 95 प्रतिशत से अधिक परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जन धन-आधार-मोबाइल ((जेएएम) त्रयी ने वित्तीय पहुँच को बेहद सरल बनाया। मई 2025 तक 55.44 करोड़ जन धन खाते खोले गए, जिनमें 56 प्रतिशत महिलाएँ हैं और खातों में रू. 2.5 लाख करोड़ से अधिक जमा है। डीबीटी ने लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाकर भ्रष्टाचार रोका। शून्य-बैलेंस खातों में रुपे कार्ड, रू. 2 लाख का दुर्घटना बीमा और छह महीने के सुचारु संचालन पर ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। साथ ही बीमा, अटल पेंशन योजना और मुद्रा ऋण जैसी योजनाएँ करोड़ों लोगों को सीधे लाभ पहुँचा रही हैं। डिजिटल भुगतान की विभिन्न प्रणालियों ने बैंकिंग को जन-सुलभ बनाया और स्ट्रीट वेंडरों, लघु उद्यमियों तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान आसान कर दिया है,जिससे धन अंतरण के पारंपरिक साधन जैसे ड्राफ्ट और मनीऑर्डर अब लगभग अप्रचलित हो गए हैं।

रिज़र्व बैंक समय-समय पर नीतिगत सुधारों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को मजबूत कर रहा है। कृषि ऋण की बिना गारंटी सीमा रू. 2 लाख तक बढ़ाई गई है, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ऋण सीमाएँ विस्तारित हुई हैं और कमजोर वर्गों की सूची भी बढ़ाई गई है। शहरी सहकारी बैंकों में

महिलाओं के लिए ऋण सीमा हटाकर उन्हें अधिक लचीलापन दिया गया है। सह- ऋण व्यवस्था का दायरा बढ़ाकर अधिक संस्थाओं को जोड़ा गया है। डिजिटल भुगतान को सरल बनाने के लिए अब प्राथमिक खाताधारक की अनुमति से दूसरा उपयोगकर्ता सीमित भुगतान कर सकता है, और विकलांगजन-अनुकूल भुगतान प्रणालियाँ विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।

वित्तीय साक्षरता के बिना समावेशन अधूरा है। रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण और शहरी जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित किए हैं। वित्तीय साक्षरता केंद्र किसानों, महिलाओं और उद्यमियों को वित्तीय शिक्षा और परामर्श प्रदान करते हैं, जिसमें बचत, ऋण, बीमा और डिजिटल भुगतान की जानकारी शामिल है; बैंक और एनजीओ मिलकर कार्यशालाएँ और परामर्श चलाते हैं, जिससे समावेशन और सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ती है।

भारत में वित्तीय समावेशन की प्रमुख चिंताएँ हैं–गहरी क्षेत्रीय व लैंगिक असमानताएँ, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में नकदी-निर्भरता, कम वित्तीय साक्षरता और कमजोर ऋण अभिगम्यता, जिनके साथ भ्रष्टाचार व संस्थागत शासन की खामियाँ बीमा उत्पादों की अनुचित, बिक्री, डिजिटल धोखाधड़ी, माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में अति-ऋणग्रस्तता और कठोर वसूली प्रथाएँ स्थिति को और जटिल बनाती हैं। इसलिए बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन, वित्तीय अनुशासन, नैतिकता युक्त कम खर्चीली वसूली और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना अत्यावश्यक है।

भारत में वित्तीय समावेशन का भविष्य उभरती तकनीकों– ऐआई, ब्लॉकचेन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अकाउंट एग्रीगेटर और यूनिफ़ाइड लेंडिंग इंटरफेस–के प्रभावी उपयोग पर आधारित है। जेएएम-यूपीआई-यूएलआई जैसे नए मॉडल वित्तीय पहुँच, क्रेडिट वितरण और सेवा-गुणवत्ता को और सरल बनाते हुए, इंडिया स्टैक के माध्यम से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता व दक्षता बढ़ा रहे हैं। बैंक भी दूरस्थ क्षेत्रों के लिये हल्के और उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल उत्पाद विकसित कर रहे हैं, जिससे हर नागरिक तक सुरक्षित और भरोसेमंद वित्तीय सेवाएँ पहुँच सके। आगे की प्राथमिकता डिजिटल ढाँचे और वित्तीय साक्षरता के विस्तार, किसानों- मध्यम उद्योगों के लिये लचीली ऋण व्यवस्था, तथा मजबूत नियामक शासन और महिला-केंद्रित नीतियों में समन्वय पर होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस हमें याद दिलाता है कि बैंक केवल पूंजी निर्माण करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, मौद्रिक नीति लागू करवाने और बचत को प्रोत्साहित करने वाली आर्थिक संस्थाएँ ही नहीं, बल्कि समाज के व्यापक विकास के महत्वपूर्ण वाहक भी हैं। भारत ने वित्तीय समावेशन में नवाचार के माध्यम से दुनिया को–'इनोवेशन विद इंक्लूजन' का प्रभावशाली मॉडल दिया है । आज करोड़ों लोग, जो पहले बैंकिंग से बाहर थे, अब वित्तीय मुख्यधारा में आ चुके हैं। वित्तीय समावेशन में विशेष रूप से महिलाएँ और ग्रामीण युवा शामिल हैं, जो आर्थिक निर्णय लेने और अधिक सशक्त बन रहे हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मजबूती, नवाचार और भरोसेमंद सेवाएँ इस समावेशन को स्थायी और प्रभावशाली बनाती हैं। यही समावेशन भारत को अधिक समृद्ध, समान और सशक्त बनाता है। भविष्य का भारत तभी सच में समावेशी होगा, जब कोई भी नागरिक वित्तीय मुख्यधारा से बाहर न रहे। अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस याद दिलाता है कि लक्ष्य सरल है–हर हाथ तक पहुँच, हर सपने को पूँजी।

श्री दत्तात्रेय जयंती विशेष

अमित राव पवार

युवा साहित्यकार

नव पीढ़ी के लिए भगवान दत्तात्रेय से मिलने वाली प्रेरणा

लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूरी बना ले तो एक सशक्त,विवेकशील और चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण संभव है। भगवान दत्तात्रेय केवल देवता नहीं हैं, बल्कि एक जीवन दर्शन हैं - जो हमें आत्म-ज्ञान, सेवा और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं। आज की पीढ़ी के नाम श्री दत्तात्रेय का संदेश 'संकट चाहे जितना बड़ा हो यदि मन शांत है, तो समाधान निश्चित है।' प्रकृति से जुड़ो,सत्य को अपनाओ, और भीतर के गुरु को पहचानो- वही भगवान है। भगवान दत्तात्रेय का जन्म मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में माना जाता।तभी से इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से तीनों देवों की पूजा करने से फल प्राप्त होता है, इनके सारथी के रूप में गौ माता और श्वान दोनों को माना जाता।

वर्तमान का युवा आधुनिकता की मौज-मस्ती में इतना खोता जा रहा कि उसे भविष्य और अपने आसपास की जटिल समस्याओं का आभास ही नहीं हो रहा है। जैसे हिरण अपनी मस्ती में इतना खो हो जाता, कि उसे अपने ईदगिर्द शेर होने का अंदेशा ही नहीं चलता और वह परेशानियों में फंस जाता है आज का युवा भी कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। अनेक चुनौतियों,भ्रम और प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय का जीवन दर्शन एक मजबूत मार्गदर्शक बन सकता है। उन्होंने यह सिखाया कि ज्ञान किसी एक स्थान, व्यक्ति या ग्रंथ में सीमित नहीं होता,बल्कि वह प्रकृति के हर कण में फैला है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश,पशु-पक्षी, मधुमक्खी, बालक, वेश्या, कछुआ, मछली जैसे सामान्य से प्रतीत होने वाले तत्वों को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया। यह संदेश आज की पीढ़ी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सीखने के लिए उम्र, जाति, पद या आधार की आवश्यकता नहीं होती। जो हमें जीवन का एक भी सत्य सिखा दे, वही हमारा गुरु हो सकता है। असफलता भी सबसे बड़ी शिक्षिका बन सकती है,अगर हम उसे स्वीकार करना सीख लें। भगवान दत्तात्रेय का जीवन सरलता, वैराग्य और आत्मानुशासन का प्रतीक है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखा। यह आज के युवाओं को यह सिखाता है कि भोग की अंधी दौड़ से आगे निकलकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। वर्तमान समय में जहाँ लोग तनाव, अवसाद और निराशा का शिकार हो रहे हैं,वहीं भगवान दत्तात्रेय का दर्शन हमें यह सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। उनकी उपासना मन को स्थिर, दृढ़ और सकारात्मक बनाती है।

यदि युवा पीढ़ी ऱसत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सीख ले,अपने माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। प्रकृति से जुड़कर जीवन जीना सीख ले। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूरी बना ले तो एक सशक्त, विवेकशील और चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण संभव है। भगवान दत्तात्रेय केवल देवता नहीं हैं, बल्कि एक जीवन दर्शन हैं- जो हमें आत्म-ज्ञान, सेवा और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं। आज की पीढ़ी के नाम श्री दत्तात्रेय का संदेश 'संकट चाहे जितना बड़ा हो यदि मन शांत है, तो समाधान निश्चित है।' प्रकृति से जुड़ो, सत्य को अपनाओ, और भीतर के गुरु को पहचानो- वही भगवान है। भगवान दत्तात्रेय का जन्म मार्गशीर्ष माह की

पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में माना जाता। तभी से इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से तीनों देवों की पूजा करने का फल प्राप्त होता है,इनके सारथी के रूप में गौ माता और श्वान दोनों को माना जाता। मान्यता के अनुसार विष्णु के छठे अवतार इन्हें कहा जाता है। तीनों शक्तियों में समाहित भगवान दत्तात्रेय सर्वव्यापी हैं, उनकी उपासना से मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। भगवान दत्तात्रेय में तीन पहलु-सृजन,पालन एवं विलय का एकीकरण है। माँ व पुत्र के मध्य कैसा मार्मिक संबंध होता है,इस बात को अनुसूया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश के माध्यम से इस संसार को बताने का प्रयास किया है। श्री दत्तात्रेय भगवान को संसार ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के संयुक्त रूप में पूजन करता। त्रिदेव का यह शक्ति स्वरूप अवतार देव एवं गुरु दोनों है। भारतीय सनातन हिंदू परंपरा के अखाड़े में भगवान दत्तात्रेय को अपना पूजनीय माना गया साथ ही सांसारिक जीवन में गुरु रूप में इन्हें हम अपना इष्ट देव मानते भगवान श्री दत्तात्रेय अपने समीप कामधेनु,गौ माता को रखकर, औदुम्बर के वृक्ष में विराजित होकर अनंत काल तक इस संसार को प्रकृति के साथ रहने का संदेश दे रहे, साथ ही उनके आसपास चार श्वान वेदों के प्रतीक माने जाते हैं।

भगवान दत्तात्रेय अवधूत रूप में भी है। अर्थात् जो अंह को समाप्त करता है अनेक बार हम स्वयं पर अभिमान करते हैं,जब मनुष्य स्वयं पर अभिमान करने लगते है तो उसके पुण्य श्रीण होने लगते है हमारे भीतर करुणा का भाव सूखने लगता, भगवान का स्वरूप मनुष्य को इस बात की स्मृति करता है कि अंह को अलग रखकर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे। भगवान दत्तात्रेय के भारत में 16 महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं, उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में 24 गुरुओं को स्वीकार किया, जिससे जो ज्ञान पाया उसे गुरु रूप में अपनाया यह वर्तमान परिस्थितियों में युवाओं को संदेश है कि हम इस संसार के हित ओर सकारात्मकता लिए जिससे भी कुछ सीखते हैं वह हमारे लिए गुरु, पूजनीय, आदरणीय,सम्माननीय होते है। नव पीढ़ी को चाहिए कि वह दिखावे की दुनिया से निकलकर सादगी, ज्ञान और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाए यही श्री दत्तात्रेय जयंती का सच्चा संदेश है।

गन्ना के खेत में टाइगर के पगमार्क मिले, सर्चिंग शुरू

रातामाटी में तीन टीमें तैनात, ग्रामीणों को खेतों में न जाने की सलाह

बैतूल। चिचोली रेंज के रातामाटी खुर्द गांव के गन्ना खेतों में टाइगर की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग ने तत्काल सर्चिंग शुरू कर दी है। पश्चिम वन मंडल के डीएफओ के निर्देश पर तीन टीमें गठित कर तलाशी अभियान चला रही हैं। ग्रामीणों ने तीन दिन

पहले रविवार रात टाइगर की हलचल देखी थी, जिसकी जानकारी चिचोली रेंज कार्यालय और डीएफओ को दी गई। मौके पर पहुंची टीम को किसान राजेश यादव के गन्ना खेत में टाइगर के स्पष्ट पगमार्क मिले हैं। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को भी संभावित क्षेत्रों में सर्चिंग जारी रही। वन विभाग ने रातामाटी खुर्द और आसपास के गांवों में मुनादी कर ग्रामीणों को रात में खेतों में न जाने की सलाह दी है। हालांकि, रात में सिंचाई के लिए खेतों में जाना किसानों की मजबूरी है, जिससे उनमें सतर्कता बनी हुई है। राजेश यादव ने बताया कि उनके गन्ने के खेत में अभी भी टाइगर मौजूद है। जानकारों के अनुसार, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र से हर साल नवंबर-दिसंबर में टाइगर का मूवमेंट देखा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि टाइगर ने किसी जानवर का शिकार किया होता, तो वह लंबे समय तक उसी क्षेत्र में रहता, अन्यथा वह आगे बढ़ जाता है। अभी तक किसी शिकार की सूचना नहीं मिली है।

बैतूल जिले ने शत-प्रतिशत डिजिटलाइज्ड का कार्य पूर्ण कर मप्र में पाया द्वितीय स्थान

एसआईआर : 100 फीसदी डिजिटलाइजेशन पूर्ण, 94.44 प्रतिशत मैपिंग का कार्य

बैतूल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य 4 नवंबर से शुरू हुआ। गणना पत्रक मिलने के बाद 10 नवंबर से बीएलओ ने घर-घर जाकर सर्वे कार्य किया। हालांकि कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के सतत निगरानी व टीम वर्क की मेहनत से निर्धारित समय सीमा के पहले ही जिले ने एसआईआर के डिजिटलाइज्ड लक्ष्य पूरा कर लिया है। 4 दिसंबर तक यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन इससे पहले ही जिले ने डिजिटलाइज्ड का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर मध्यप्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। एसआईआर के कार्य में सभी ने कठिन चुनौती को सरलता से पूरा कर अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिसके लिए कलेक्टर ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद के सीईओ, नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि इस श्रेष्ठ उपलब्धि के पीछे बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलओ, शिक्षक, पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, कोटवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

जिले में 11 लाख 88 हजार मतदाताओं की मैपिंग - बताया जा रहा है कि जिले के 12 लाख 58 हजार 295 मतदाताओं में से 11 लाख 88 हजार 296 मतदाताओं में (94.44 प्रतिशत) मैपिंग का कार्य अब तक पूर्ण कर लिया गया है। मैपिंग से शेष मतदाताओं को भी जानकारी प्राप्त कर लगातार मैपिंग की जा रही हैं। साथ ही मृत,

अनुपस्थित और स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं का पुनः परीक्षण भी कराया जा रहा हैं। बता दे कि आदिवासी बाहुल्य जिले में पहाड़ी अंचल होने के बावजूद जिले के बीएलओ व सहयोगी दल लक्ष्य पूरा करने लिए दिन रात एक कर दिया। जिससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य तय समय से पहले पूरा हो पाया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का जिले में गंभीरता से पालन किया जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बैतूल जिले ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम में संशोधन करते हुए सभी चरणों की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। आयोग द्वारा जारी नवीन एसआईआर कार्यक्रम के अनुसार घर-घर गणना पत्रक एवं सत्यापन का कार्य अब 11 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद प्रारूप मतदाता सूची 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएँगी। संशोधित कार्यक्रम अनुसार दावे और आपत्तियों पर सुनवाई, सत्यापन, प्रपत्रों की जांच तथा निर्णय प्रक्रिया निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक निरंतर रूप से की जाएगी। संशोधित कार्यक्रम अनुसार जांच और अंतिम प्रकाशन की अनुमति के लिए आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव की समय-सीमा 10 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

नागपुर-अमरावती ने एसआईआर में बीएलओ का बढ़ाया सरदर्द

- 2003 की मतदाता सूची नहीं मिलने से हो रही समस्या
- महाराष्ट्र से आई कई बहुओं के गणना प्रपत्र अटके

आमला। पूरे प्रदेश में विशेष मतदाता सूची परीक्षण के अभियान में अपना अग्रणी स्थान बना चुकी आमला विधानसभा और अभियान में लगी निर्वाचन की पूरी टीम ने जो उदाहरण पेश किया है, उसको सराहना मिलनी भी चाहिए। इस अभियान के लिए निर्वाचन द्वारा दिए गए महज एक माह के दस दिन पूर्व ही सौ फ़ीसदी कार्य को अंजाम देने वाली आमला निर्वाचन टीम और उनके कप्तान एसडीम शैलेंद्र बडोनिया पूरे देश के लिए एक नजीर पेश कर चुके हैं। किंतु इसके बावजूद भी महाराष्ट्र निर्वाचन की साइट नहीं खुलने से दर्जनों मामलों पर पेंच फंस गया है। दरअसल महाराष्ट्र से सटी सीमा होने के चलते आमला विधानसभा इलाके में यहां महाराष्ट्र इलाके से आई दर्जनों बहुओं के 2003 की मतदाता सूची की जानकारी नहीं मिल पाने से समस्या हो रही है, हालांकि निर्वाचन शाखा आमला में दर्जनों कर्मचारी अभी भी नई मतदाता सूची के लिए कई कई घंटे तक काम कर रहे है। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आमला मतदाता विशेष पुनरीक्षण का कार्य पूरी तरह निर्विघ्न संपन्न हो चुका है। शहर और आसपास के इलाके में भारत के विभिन्न प्रांतो से मतदाताओं की 2003 की सूची भी निर्वाचन की विभिन्न साइटों के माध्यम से मिल चुकी है, किंतु अमरावती के मोर्शी और नागपुर के कुछ इलाकों की साइट नहीं खुल पाने से समस्या बन रही है।

विश्व विकलांग दिवस पर खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

शाहपुर। विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में विकासखण्ड स्तरीय दिव्यांग बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता बीआरसी कार्यालय परिसर में आयोजित की गई। जिसमें विकासखण्ड की शालाओं में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों ने विभिन्न विधाओं में भाग लेकर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सम्मिलित समस्त प्रतिभागियों एवं उनके पालकों और शिक्षकों को भोजन कराया गया। विभिन्न विधाओं में चयनित बच्चों को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शाहपुर जीआर बर्डे, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक आरएल भादे द्वारा पुरूस्कार वितरण किया गया। मोबाइल स्त्रोत समन्वयक अजय लाल द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता की रूपरेखा बतायी गयी। अंत में बीएसी आशा कावरे द्वारा आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया गया।

मप्र कांग्रेस कार्यालय में बहुप्रतीक्षित पॉडकास्ट स्टूडियो का शुभारंभ

भोपाल। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मुद्दा-आधारित संवाद को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए पॉडकास्ट स्टूडियो रूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। यह महत्वपूर्ण पहल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के मार्गदर्शन तथा संगठन प्रभारी डॉ. संजय कामले जी के प्रभावी प्रयासों से संभव हुई। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के प्रथम तल पर विकसित इस आधुनिक एवं सुसज्जित पॉडकास्ट स्टूडियो का उद्देश्य पार्टी की नीतियों, जनसरोकार से जुड़े मुद्दों और संगठन की आवाज़ को तकनीकी रूप से और अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुँचाना है। यह स्टूडियो कांग्रेस संगठन को डिजिटल युग में सशक्त संवाद का नया माध्यम प्रदान करेगा।कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश पदाधिकारी, विभिन्न विभागों एवं प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और सभी ने इस पहल को संगठन के लिए दूरगामी एवं अत्यंत आवश्यक कदम बताया। इस शुभ अवसर पर प्रमुख रूप से पीसीसी चीफ श्री जीतू पटवारी,सीएलपी लीडर श्री उमंग सिंघार,पूर्व मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा,मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री मुकेश नायक,पूर्व मंत्री श्री जयवर्धन सिंह, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रांत भूरिया,विधायक श्री महेश परमार, सीडब्ल्यूसी सदस्य श्री ओमकार मकरम,पूर्व मंत्री श्री लखन घनघोरिया, संगठन प्रभारी डॉ. संजय कामले,सेवादल के अध्यक्ष श्री अवनीश भार्गव,प्रशिक्षण प्रभारी श्री महेंद्र जोशी,भोपाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रवीण सक्सेना,महासचिव श्री संजीव सक्सेना उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी ,नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, सहित वरिष्ठ नेताओं ने शुभकामनाएं दी और संयुक्त रूप से कहा कि यह पॉडकास्ट स्टूडियो संगठन को नई ऊर्जा देगा तथा जनता से संवाद को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाएगा।

एचआईवी एड्स को हराने के लिए जागरूकता जरूरी

- रेल्वे स्टेशन पर एड्स को लेकर चलाया जागरूकता अभियान

बैतूल। विश्व एड्स दिवस 2025 के अवसर पर मप्र राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के तत्वावधान में जिला एड्स नियंत्रण समिति के मार्गदर्शन में लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना योर्स सोशल सोसायटी बैतूल द्वारा साप्ताहिक जनजागरुकता कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को रेल्वे स्टेशन बैतूल में रेल्वे हम्माल यूनियन और जनसमुदाय को एचआईवी एड्स, टीबी, हेपेटाइटिस बी से बचाव के प्रति जागरूक किया। जिसमें एचआईवी के 4 कारण एवं इनके बचाव के तरीके के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया एवं एचआईवी एक्ट

2017 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम बाधाओं को दूर करना, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन लाना रही। जिसके तहत एचआईवी-एड्स की रोकथाम, बचाव, उपचार और जागरूकता से जुड़ी विस्तृत जानकारी लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के स्टाफ द्वारा प्रदान की। उन्होंने एचआईवी संक्रमण के तरीकों, सुरक्षित व्यवहार, मिथक और वास्तविकताओं, तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर प्रकाश डाला। रेल्वे स्टेशन प्रबंधक ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से एचआईवी-एड्स को लेकर जागरूकता बढ़ना, भ्रांतियों को दूर करना और युवाओं को सुरक्षित व्यवहार के प्रति सजगता बढ़ेगी। इस अवसर पर लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना योर्स सोशल सोसायटी की काउंसलर श्रीमति प्रीति बाला पवांर एमएडई वैभव मालवी, ओआरडब्ल्यु भाग्यश्री तालमपुरिया, छाया प्रजापति, भाग्यश्री नामदेव, अभिषेक सोनी, सरिता बोडखे, कीर्ति प्रमिला मसौदकर एवं रेल्वे स्टाफ, प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित रहे।

महिला कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी का भोपाल में भव्य स्वागत,पदभार ग्रहण किया

भोपाल(नप्र)। महिला कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी बुधवार को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। रीना बौरासी अपने समर्थकों के साथ इंदौर से भोपाल तक रैली निकाली। इंदौर -उज्जैन से देवास, सोनकक्ष, आष्टा, सीहोर होते हुए भोपाल आएंगी। भोपाल पहुंचने के बाद राजधानी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।

घोघरी मध्यम परियोजना की टेस्टिंग और ट्रायल 30 दिसंबर तक पूर्ण की जाए : जल संसाधन मंत्री

जिले की मेंढ़ा एवं गढ़ा मध्यम परियोजनाओं को जून-2026 तक पूर्ण करने के निर्देश

बैतूल। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की अध्यक्षता में जल परियोजनाओं की प्रगति को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बैतूल हेमन्त खंडेलवाल, आमला विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे, विधायक मुलताई चंद्रशेखर देशमुख, विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान, विधायक घोड़ाडोंगरी श्रीमती गंगाबाई उईके तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक श्री खंडेलवाल की पहल पर बैतूल जिले की सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए यह विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैतूल जिले की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने घोघरी मध्यम परियोजना की टेस्टिंग और ट्रायल 30 दिसंबर 2025 से पहले हर हाल में पूर्ण किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि पारसडोह परियोजना की सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करें एवं निर्गुड प्रोजेक्ट को शीघ्र पूर्ण करें। इसके अलावा उन्होंने मेंढ़ा मध्यम परियोजना का कार्य जून 2026 तक पूर्ण करने तथा अतिरिक्त 4500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ाने के संबंध में आवश्यक प्रस्ताव एवं कार्यवाही शीघ्र तैयार करने के लिए जल संसाधन विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं गढ़ा मध्यम परियोजना को भी जून 2026 से पहले पूर्ण करने के लिए विभाग को तेजी से काम बढ़ाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि जिले में चल रही हर जल परियोजना किसानों और ग्रामीणों के हित से जुड़ी है, इसलिए काम की रफ्तार तेज की जाए और निर्धारित समयसीमाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

शीतलझिरी परियोजना के लिए मिलेगा विशेष पैकेज - बैठक के दौरान मंत्री श्री सिलावट ने जिला जनजातीय बहुल क्षेत्र होने के कारण शीतलझिरी मध्यम परियोजना के लिए विशेष पैकेज पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की स्वीकृति के लिए आवश्यक प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों को दीर्घकालिक लाभ मिल सके। मंत्री श्री सिलावट ने शेष विधानसभा वार विधायकों की मांग पर नवीन योजनाएं बनाने के भी निर्देश दिए। मंत्री श्री सिलावट ने बैतूल जिले के हर विधानसभा क्षेत्र से 5-5 नई जल योजनाएं (बैराज, जलाशय) चिन्हित कर इन योजनाओं की साध्यता और स्वीकृति की कार्रवाई जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचे और किसानों को सिंचाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए, इसके लिए जिले के विभिन्न जलाशयों की नहरों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए आर आर आर योजना के तहत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

6 दिसंबर को आयोजित होगा श्रम सम्मेलन

सारनी। नगरपालिका परिषद सारणी में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगरीय निकायों के प्रदेश प्रभारी हरिओम कुशवाह, नगरपालिका मज़दूर संघ के जिला अध्यक्ष केके भावसार ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 6 दिसंबर को भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री पंजाब गायकवाड़ के निर्देशन में कुलदीप गुर्जर प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ की अध्यक्षता में आयोजित श्रम सम्मेलन में शामिल होगे। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सभी संगठनों के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में बैतूल पहुंचकर संशोधित श्रम कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करे। अपने अधिकार को जाने और नए श्रम कानून के मुताबिक श्रमिकों के हित में काम करे। बैठक में नगरपालिका मज़दूर संघ से गुणवन्त हुरमाडे, संदीप डोंगरे, मिथुन नकवाल, राजकुमार गवांडे ठेका मजदूर संघ, आंगनवाड़ी संघ के पदाधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। श्री भावसार ने बताया कि श्रम सम्मेलन में जिले की सभी 8 नगरपालिका, नगर परिषद के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे एवं कर्मचारियों की विभिन्न मांगों से अवगत करवाकर प्रदेश महामंत्री को ज्ञापन देंगे।

नेशनल लोक अदालत के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

बैतूल। जिला मुख्यालय बैतूल एवं सिविल न्यायालय आमला, भैंसदेही तथा मुलताई में 13 दिसंबर 25 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा बुधवार को 07

प्रचार वाहनों को जिला न्यायालय परिसर बैतूल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विद्युत विभाग, नगर पालिका के प्रचार वाहन बैतूल शहर के लगभग सभी वार्डों एवं मुख्य सडक़ों व शहर की गलियों में नेशनल लोक अदालत के आयोजन एवं इसके लाभ के बारे में लोक अदालत जिंगल द्वारा प्रचार-प्रसार करेगें। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश सचिन कुमार घोष, कैलाश नारायण अहिरवार, डॉ. कु. महजबीन खान, श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती संगीता भारती राठौर, न्यायाधीश /रजिस्ट्रार सुरेश यादव तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय, विद्युत विभाग डीजीएम योगेन्द्र चौधरी तथा अन्य न्यायाधीशगण व लीगल एड डिफेंस काउंसल तथा न्यायालय, विद्युत तथा नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित रहे।

दो दिवसीय प्रथम जिला स्तरीय डाक टिकिट प्रदर्शनी 17 दिसंबर से

बैतूल। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में विरासत के रंग, डाक के संग थीम पर प्रथम जिला स्तरीय डाक टिकिट प्रदर्शनी छिन्दपेक्स-2025 का आयोजन 17 दिसंबर से 18 दिसंबर तक किया जाएगा। भारतीय डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित डाक टिकिट प्रदर्शनी में जिले अंतर्गत एवं समीपवर्ती जिलों के डाक टिकिट संग्रहकर्ता जिनमें स्कूल, कॉलेज के छात्र, युवा तथा नागरिक एवं फिलाटेलिस्ट को उनके द्वारा संग्रह किए हुए डाक टिकिटों को डाक टिकिट प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा। जिला स्तरीय डाक टिकिट प्रदर्शनी के दौरान छिंदवाड़ा जिले के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल पातालकोट-तामिया पर एक विशेष आवरण का विमोचन किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों के लिए स्टैम्प डिजाइन और क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों की डाक टिकिट प्रदर्शनी स्थल पर शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जाएगा। जिससे भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को डाक टिकिटों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी।

चिचोली में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

बैतूल। तहसील मुख्यालय चिचोली में किसानों की बिजली समस्या, खाद की कालाबाजारी, समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी की गड़बडियों तथा बिजली विभाग द्वारा किसानों से की जा रही अवैध वसूली के विरोध में किसान कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष जगदीश गोचरे के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। जगदीश गोचरे ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान सात दिवस के भीतर नहीं किया गया, तो किसान कांग्रेस जिले में उग्र आंदोलन और चक्का जाम करने को बाध्य होगी। उन्होंने कहा कि किसान लगातार परेशान हैं, लेकिन विभाग समस्या सुलझाने की बजाय मनमानी पर उतारू है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व आपूर्ति निगम राज्य मंत्री राजेंद्र जायसवाल, कांग्रेस प्रदेश सेवादल महासचिव मनोज आर्य, प्रदेश किसान नेता अक्कू पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र आर्य, भीमपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चुन्नीलाल यादव, शहरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय आर्य, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नेकराम यादव, किसान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता तोप पटेल, पूर्व जनपद अध्यक्ष सुरका सिंह उइके, युवा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सोनू, शिवम गिरी गोस्वामी, एससी प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष श्याम, चौकी के सरपंच पति दल्लू उइके सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। इस आंदोलन को सफल बनाने में राजेश बाबा साहू की अहम भूमिका रही, जिन्होंने कार्यक्रम में किसानों को संगठित करने से लेकर ज्ञापन सौंपे जाने तक सक्रिय योगदान दिया।

कलेक्टर ने एसआईआर का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण करने पर अधिकारियों-कर्मचारियों और मतदाताओं को दी बधाई

टीम भावना और जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने से ही प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होती है और जनता को बेहतर सेवाएं मिलती : कलेक्टर

- जिले में भावान्तर योजना के सुचारू संचालन के दिए निर्देश
- शिक्षक समय पर स्कूल पहुँचें और ई-अटेंडेंस अनिवार्य रूप से दर्ज करें - कलेक्टर
- वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में तेजी लायें - कलेक्टर
- टीएल बैठक आयोजित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी विभागों के समय-सीमा वाले प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और समय सीमा के भीतर सभी प्रकरणों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें प्राथमिकता से बंद कराई जाएं। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सीहोर जिले द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने पर इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए जिले के सभी ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ सहित सीहोर जिले की पूरी टीम एवं मतदाताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सीहोर जिले की टीम ने अनुशासन, समर्पण और टीमवर्क का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह उपलब्धि जिले की मजबूत प्रशासनिक क्षमता और मतदाताओं के सहयोग का परिणाम है। कलेक्टर ने मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी जागरूकता और सक्रिय भागीदारी का इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सभी विभाग भविष्य में भी इसी तत्परता और दक्षता के साथ कार्य करते रहेंगे, जिससे जिले के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि एसआईआर का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण होने के बाद अब नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित सभी राजस्व संबंधी कार्यों का तेजी से निपटारा किया जाए, ताकि आमजन को समयबद्ध सेवाएं मिल सकें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि विभागीय प्रयासों को मजबूत करते हुए निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण बढ़ाने तथा बकाया वसूली अभियान को गति देने के निर्देश भी दिए। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि पंचायत भवनों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए, ताकि पंचायत भवनों का उपयोग मूल उद्देश्य के अनुरूप हो सके। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इछावर जनपद में चार तथा सीहोर जनपद में दो नए पंचायत भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन विभाग से आवश्यक अनुमति शीघ्र प्राप्त की जाए, ताकि निर्माण कार्य समय पर प्रारंभ हो सके।

भावान्तर योजना के सुचारू संचालन के निर्देश

जिले में सोयाबीन उपार्जन एवं भावान्तर भुगतान योजना के सुचारू संचालन के लिये कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि भावान्तर योजना का सुचारू संचालन नोडल अधिकारी स्वयं सुनिश्चित करें। उन्होंने मंडी प्रबंधन को निर्देशित किया कि यदि सोयाबीन की आवक पंजीयन से अधिक पाई जाती है, तो तत्क्षण आवश्यक कार्यवाही की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान तत्काल कराया जाए। जिन किसानों के भुगतान लंबित या फेल हो गए हैं, उनके मामलों का तत्काल निराकरण किया जाए।

शिक्षक समय पर स्कूल पहुँचें और ई-अटेंडेंस अनिवार्य रूप से दर्ज करें

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के सभी शिक्षक समय पर विद्यालय पहुँचकर अपनी ई-अटेंडेंस अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उपस्थिति दर्ज कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए समयपालन एवं डिजिटल उपस्थिति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में तेजी लायें

कलेक्टर श्री बालागुरू के ने वन, राजस्व एवं जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन ग्रामों से राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन की कार्यवाही में तेजी लाई जाए, ताकि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं और शासकीय योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल सके। उन्होंने कहा कि लंबित वनाधिकार पट्टों तथा सामुदायिक दावों का शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने वन ग्रामों में सीमा निर्धारण का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने तथा समुचित अभिलेख तैयार करने हेतु राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आज से बड़े तालाब में तैरेंगे 20 शिकारे, मिलेगा डल झील जैसा नजारा

सीएम करेंगे लोकार्पण, बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के विधायक होंगे शामिल

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बड़े तालाब पर गुरुवार से 20 शिकारे तैरना शुरू होंगे। ये शिकारे श्रीनगर की डल झील की तरह लोगों को नया अनुभव देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 9 बजे मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ इसका उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी शामिल होंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के विधायक भी आमंत्रित हैं।

इसके बाद आम लोग शिकारे का लुत्फ उठा सकते हैं। इससे पहले नगर निगम ने 13 जून-24 में प्रायोगिक तौर पर एक शिकारा चलाया था। इसके बाद अब एक साथ 20 शिकारे बड़ा तालाब में उतारे जाएंगे। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने करीब 10 महीने, 12 सितंबर को क्रूज और मोटर बोट पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सामान्य बोट ही चलाई जा रही है।

ये रहेगा किराया

नगर निगम ने पिछले साल स्थानीय रजिस्टर्ड मछुआरे से एक शिकारा तैयार कराया था। नाव को शिकारे की तर्ज पर सजाया गया था। इस प्रयोग के बाद अब 20 शिकारे एक साथ बड़ा तालाब में उतारे जाएंगे। प्रति व्यक्ति किराया करीब 150 रुपए होगा। वहीं, यह 2.3 किलोमीटर का राउंड लगाएगा।

सुबह 7 से शाम 7 बजे तक चलाए जाएंगे

जानकारी के अनुसार, शिकारे में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक चलाए जाएंगे। ऐसे में यह बीच में स्थित टापू के करीब भी पहुंचेगा। हालांकि, अभी किराया तय नहीं हुआ है। गुरुवार को तस्वीर साफ हो जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने पूर्व मंत्री श्री मलैया का कुशल क्षेम जाना

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बुधवार को पूर्व मंत्री श्री जयन्त मलैया के निवास पहुँचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने श्री मलैया के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विभिन्न विषयों पर श्री मलैया से चर्चा भी की।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के दिए निर्देश

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा विभागीय योजनाओं, गतिविधियों तथा योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिले में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रगति की विधानसभावार जानकारी लेते हुए एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ तथा सीएमओ को मिलकर एसआईआर अंतर्गत गणना पत्रकों का डिजिटलाईजेश कार्य को आगामी तीन दिवस में प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि एसआईआर कार्य की प्रगति की प्रतिदिन जूम वीसी के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कलस्टर विकसित किए जाने हेतु अभी तक की गई कार्यवाही की अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कहा कि आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाए। पशुपालन हेतु जिन हितग्राहियों के प्रस्ताव बैंकों को भेजे गए हैं, उनमें स्वीकृति और राशि वितरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराएं। इसी प्रकार धान के कलस्टर विकसित करने हेतु किए जा रहे कार्यो की भी जानकारी ली। साथ ही धान उपार्जन की भी जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने जैविक प्राकृतिक खेती, फूलों की खेती, सब्जी की खेती आदि के कलस्टर विकसित कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने विभागवार सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा के दौरान जनपद पंचायतों में 50 दिवस से अधिक समयावधि की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण में बेहतर कार्य होने पर सभी जनपद सीईओ की सराहना की।

उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का प्राथमिकता के साथ संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराया जाए। सीएम हेल्पलाईन शिकायत निम्नगुणवत्ता से बंद ना हो और ना ही नॉन अटेन्डेन्ट रहे। जिन विभागों में अधिक संख्या में शिकायतें लंबित हैं, वह अधिकारी प्रतिदिन शिकायतों के निराकरण की प्रगति की मॉनीटरिंग करें। बैठक में शासकीय कार्यालयों में रख-रखाव, व्यवस्थाएं, रिकार्ड संधारण आदि पर भी चर्चा कर दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय सहित जिला अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखण्डों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित अन्य अधिकारी वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का नर्मदापुरम जिले में हुआ भव्य आयोजन

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले का एसएनजी स्कूल का प्रांगण ऐतिहासिक भव्य एवं दिव्य घटना का साक्षी बना। जब यहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत संत समाज, नागरिक गण, प्रशासनिक अधिकारी एवं हजारों छात्र-छात्राओ एवं शिक्षक गणों ने सस्वर गीता के 15 वे अध्याय का पाठ किया। ऋषिकेश से पधारे स्वामी ध्रुव चैतन्य सरस्वती, इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष श्री प्रणव दास जी, आचार्य सोमेश परसाई, श्री ब्रह्मा देव शास्त्री की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में सेमेरिटर्न स्कूल के विद्यार्थियों ने श्री भगवत गीता के पंचानन पाठ की स्तुति की। सभी मुख्य अतिथियों ने श्रीमद् भगवत गीता एवं भगवान कृष्ण के चित्र पर दीप प्रजवलन कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गुफा आश्रम की राधा मुनी, पंडित गोपाल प्रसाद खडडर, नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु जैन,संयुक्त आयुक्त विकास श्री जी सी दोहर, नगर पालिका नर्मदापुरम की अध्यक्ष श्रीमती नीतू महेंद्र यादव, जन अभियान परिषद के संभागीय अधिकारी श्री कौषलेश तिवारी, श्री पवन सहगल, स्कूली छात्र-छात्राएं, शिक्षक गण, प्रशासनिक अधिकारी गण एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार गण उपस्थित रहे।

श्रीमद् भगवत गीता की अमर वाणी सत्य से साक्षात्कार कराती है : ग्वालियर जिले से आए गीता प्रेस के आचार्य ब्रह्मदेव शास्त्री ने श्रीमद् भगवत गीता के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के दो श्लोक पढ़ने से मन शांत रहता है। मन यहां वहां नहीं भटकता है। गीता के श्लोक सुनने से मन में स्थिरता आती है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों का आह्वान किया कि वह नित्य गीता का पाठ करें साथ ही अपने नित्य नियम दायित्वों का भी पूर्ण रूप से पालन करें। उन्होंने कहा कि भारतवासी विकास भी करेंगे और अपने इतिहास को आगे भी बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य नई पीढ़ी के पास श्रीमद् भगवत गीता को पहुंचाना है ताकि नई पीढ़ी श्रीमद् भगवत गीता की अमरवाणी से साक्षात्कार कर सके। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन एवं विश्व गीता प्रतिष्ठान का यह संयुक्त प्रयास है की गीता घर-घर पहुंचे और इसका सभी लोग अध्ययन करें।

ऋषिकेश के सुबोधनंद फाउंडेशन के अध्यक्ष स्वामी ध्रुव चैतन्य सरस्वती ने श्रीमद भागवत गीता की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस तरह एक माली अपने उपवन में अलग-अलग तरह के बीज लगाता है। बीज को पौधों में परिवर्तित करता है। कालांतर में वह बीज एक वृक्ष का रूप धारण करता है। बच्चे ऐसे ही एक वृक्ष के समान है। बच्चे यदि गीता की छत्रछाया में बढ़ेंगे तो एक अच्छा मनुष्य बनेंगे। उन्होंने कहा कि आज वर्तमान में आवश्यकता है की माता-पिता स्वयं गीता का अध्ययन करें और गीता के उपयोगी सूत्र अपने बच्चों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि आज गीता का पाठ करने वाले सभी बच्चे खुश किस्मत हैं जिन्होंने गीता का पाठ कर अपने को पहचाना है। उन्होंने कहा कि कक्षा दसवीं तक के बच्चे यह निश्चित कर लें की उन्हें भविष्य में क्या बनना है और उस लक्ष्य को लेकर अपने माता-पिता एवं शिक्षक के दिखाएं मार्गदर्शन में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल जीवन यापन के लिए नहीं है अपितु यह मनुष्य को अपने अंदर आत्म साक्षात्कार करने का भी अवसर देती है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का अध्ययन करें तो यह पता चलता है कि उनमें बड़ों से आशीर्वाद लेने की कला विद्यमान थी। स्वामी ध्रुव चैतन्य सरस्वती ने कहा कि जो बच्चे अपने माता-पिता व गुरु का आदर नहीं करते हैं वह जीवन में सफल नहीं होते हैं। उन्होंने सभी बच्चों से कहा कि वे गीता को अपने हृदय में धारण करें, समाहित करें। गीता को पढ़ते रहे, सुनते रहे एवं उसके दिखाएं मार्ग का अनुसरण करते रहें।

भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया गीता का उपदेश

आचार्य सोमेश परसाई ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर कृष्ण एवं भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण मोक्ष काम धार्मिक आर्थिक सूत्र को लेकर आए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर तनाव के बीच उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। संयम का उपदेश दिया। आचार्य परसाई ने कहा कि सभी अपने जीवन में गीता का एक श्लोक अपना लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले के समय श्रीमद् भगवत गीता पर बात करना कठिन था लेकिन आज हम धर्म और गीता की बात करते हैं। उन्होंने सभी बच्चों का आह्वान किया कि वह मन लगाकर विद्या अर्चन करें अपनी विद्या को व्यर्थ ना करें।

रबी फसल बीमा पाठशाला सप्ताह कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

विदिशा (निप्र)। विकासखंड नटेरन के कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा रबी वर्ष 2025-26 हेतु फसल बीमा पाठशाला सप्ताह का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, नटेरन में कृषकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि समिति के सभापति श्री गजेंद्र राजपूत और श्री यशपाल सिंह रघुवंशी के द्वारा किया गया है। प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री जगदीश गुर्जर के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय फसल बीमा समन्वयक श्री शुभम मीणा एवं श्री जितेंद्र यादव द्वारा फसल बीमा पाठशाला सप्ताह के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। बीमा योजना के उद्देश्य, लाभ, पंजीयन प्रक्रिया, दावा प्रकरण एवं जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर कृषकों को विस्तार से समझाया गया। साथ ही किसानों को समय पर बीमा कराने एवं प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले संभावित नुकसान से बचाव हेतु आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया।

आजीविका मिशन की मदद से क्रांति बाई ने शुरू किया स्वयं का व्यवसाय

रायसेन (निप्र)। आजीविका मिशन की मदद से क्रांति बाई ने शुरू किया स्वयं का व्यवसाय रायसेन, 01 दिसम्बर 2025 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर और राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका लाभ पाकर आज अनेक महिलाएं सफल उद्यमी हैं और परिवार की आर्थिक उन्नति में योगदान दे रही हैं। रायसेन जिले के उदयपुरा क्षेत्र के ग्राम नूरनगर निवासी श्रीमती क्रांति प्रजापति भी उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने स्व-सहायता समूह से जुड़ने के अपनी मेहनत और लगन से परिवार की आर्थिक स्थिति को बदला है। ग्राम नूरनगर निवासी श्रीमती क्रांति प्रजापति स्व-सहायता समूह से जुड़ने से पहले आर्थिक समस्याओं से घिरी थी। क्रांति प्रजापति एवं उनके पति मजदूरी करते थे, जिससे परिवार का खर्च भी ठीक तरह से नहीं चल पाता था। क्रांति प्रजापति को जब आजीविका मिशन के बारे में पता चला तो उन्होंने स्व-सहायता समूहों से पहले से जुड़ी महिलाओं से चर्चा की। क्रांति प्रजापति शगुन स्व-सहायता समूह से जुड़कर 13 सूत्रों का पालन करने लगी। समूह से जुड़ने के कुछ माह बाद उन्हे आरएफ, सीआईएफ की राशि प्राप्त हुई जिससे उन्होंने एक छोटी सी मनहारी की दुकान खोली व कुछ माह बाद समूह का सीसीएल कराया गया जिससे भी उन्हें भी राशि मिली।

नयागांव में बरेली-पिपरिया मार्ग पर पुल की मरम्मत के दौरान गिरा स्पॉन, मोटरसाईकल सवार चार व्यक्ति हुए घायल

रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले के बरेली के समीप नयागांव में बरेली-पिपरिया मार्ग के किमी 4/10 पर स्थित पुल के गिरने से घायल व्यक्तियों को सिविल अस्पताल में बरेली में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा बरेली सिविल अस्पताल पहुंचे तथा घायलों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही डॉक्टर्स से भी घायलों के उपचार की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके उपरांत कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने नयागांव पहुंचकर घटना स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता भी साथ रहे। इस पुल का निर्माण वर्ष 1980 में लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था तथा मार्ग वर्ष 2010 से मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संधारण में है। एडीबी योजना अंतर्गत तैयार किए गए ऋ्रल्स सॉफ्टवेयर के अनुसार पुल के सर्वे में विभिन्न अवयव यथा स्लैब के रीनफोरसमेंट में जंग, एक्सपेंशन ज्वाइंट में कचरा, प्रोटेक्शन वर्क खराब होना पाया गया था। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर पुल के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया था। पुल के संधारण के लिए 98 लाख रू की स्वीकृति 29 मई 2025 को प्रदान की गई थी। दिनांक 01 दिसम्बर 2025 को पुल की मरम्मत के दौरान बरेली साईड का एक स्पान गिर गया, जिसमें दो मोटरसाईकल पर सवार चार युवक गिर गए। जिनका उपचार बरेली सिविल अस्पताल में चल रहा है। मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित पुल के संधारण का दायित्व संबंधित फील्ड स्टॉक का है, अतः प्रबंधक श्री एए खान को निलंबित किया गया है। वर्तमान एवं तत्कालीन संभागीय प्रबंधक एवं सहायक महाप्रबंधकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। साथ ही मुख्य अभियंता श्री गोपाल सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है जो सात दिवस में जांच रिपोर्ट पेश करेगी, तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में यातायात ग्राम नयागांव में स्थित पुरानी पुलिया के माध्यम से चलाया जा रहा है। साथ ही क्षतिग्रस्त पुल के बगल में पाईप डायवर्जन बनाया जा रहा है।

विश्व एड्स दिवस पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रैली एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन

बैतूल (निप्र)। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय बैतूल परिसर में 1 दिसम्बर को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री सुधाकर पवार, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वतीबाई बारस्कर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे एवं जनपद उपाध्यक्ष श्री कृष्णा लोखंडे द्वारा भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोली एवं जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया।

कार्यक्रम में श्री सुधाकर पवार ने कहा कि हम सबकी महती जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर एड्स के प्रति समुदाय को जागरूक करें, जागरूकता से जिले में बहुतहद तक एड्स की बीमारी को नियंत्रण किया जा सकता है। हम जिले में इतनी जागरूकता लायें कि वर्ष 2026 के एड्स दिवस के पूर्व एड्स मरीजों की संख्या में कमी आ सके। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एवं सभी लोगों ने मिलकर कोविड नियंत्रण में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है, इसी तरह आशा, एएनएम एवं अन्य स्वास्थ्य विभाग का अमला एवं एड्स के प्रति समुदाय में घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करें। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ जगदीश घोरे ने बताया कि एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना है, एड्स एक गंभीर बीमारी है जो धीरे-धीरे विकराल रूप ले रही है। इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाले लोगों में एड्स के केस लगातार बढ़ रहे हैं।

एड्स के प्रति व्यापक जनजागरूकता की आवश्यकता है। हम एड्स के मरीज को सामान्य व्यक्ति की तरह ही देखें हमें एड्स मरीज को यह विश्वास दिलाना है कि वह भी सामान्य व्यक्ति की तरह जी सकता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम ''व्यवधान पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना है''। आरएमओ डॉ रानू वर्मा ने बताया कि जिला चिकित्सालय बैतूल में एआरटी सेंटर संचालित है, एचआईवी की जांच के लिए जिले में ही समस्त टेस्ट किये जा सकते हैं।

एआरटी सेंटर में परामर्श एवं दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि जिले में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत सोशल मीडिया पर पहल एप लांच किया जाएगा, जिसके माध्यम से एड्स से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। जिला नोडल अधिकारी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम डॉ आनंद मालवीय ने बताया कि शासन का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 के बाद एड्स के नये रोगी न बढ़े, एड्स वायरल डिजिज है जो एचआईवी वायरस से होती है, यह प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। इस वायरस के विरूद्ध कोई कारगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जानकारी ही इसका बचाव है, इसका सबसे सामान्य कारण असुरक्षित यौन संक्रमित है, इसके बारे में खुलकर चर्चा होना आवश्यक है। जिले में तीन वर्ष से एआरटी सेंटर संचालित है जिसमें एड्स रोगी को नियमित रूप से दवाई दी जा रही है कई मरीज हैं जो दवाई लेकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, जीवन भर दवाईयां एवं कुछ प्रकाशन के साथ एड्स का मरीज भी लंबा जीवन जी सकता है। इस अवसर पर लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना योर्स सोसायटी द्वारा उपस्थित समस्त अतिथियों को रेड रिबन लगाकर एड्स जागरूकता संदेश दिया गया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश परिहार, शल्यक्रिया विशेषज्ञ डॉ प्रदीप धाकड़, जिला चिकित्सालय के चिकित्सक, उप जिला मीडिया अधिकारी श्री महेशराम गुबरेले, डीसीएम श्री कमलेश मशीह, जिला मैनेजर श्री योगेन्द्र दवंडे, नर्सिग स्टाफ, काउंसलर श्री दिनेश भावरकर, एआरटी स्टाफ, क्षय नियंत्रण स्टाफ, लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना योर्स सोसायटी जिला समन्वयक श्री निर्देश मदरेले एवं लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के कार्यकर्ता निजी कॉलेज के नर्सिग छात्र-छात्रा, सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक छोड़ दिल्ली रवाना हुए सीएम

4 मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन का नड्डा को देंगे न्यौता, हेल्थ-सहकारिता और महिला बाल विकास विभाग का किया रिव्यू

भोपाल (नप्र)। कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक छोड़ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि डॉ. यादव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पन्ना, बैतूल, कटनी और धार में पीपीपी मोड पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन कार्यक्रम का न्यौता देने गए हैं। इससे पहले डॉ. यादव ने स्वास्थ्य, सहकारिता और महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की है। वे लाड़ली लक्ष्मी योजना में ड्राप ऑउट से नाराज हुए। उन्होंने तीन साल में कुपोषण समाप्त करने का टारगेट महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया है। ये बैठकें मंत्रालय में चल रही थीं। जिनमें सरकार के 2 साल के कामकाज का लेखा-जोखा लिया जा रहा था।

सीएम ने बाल विकास विभाग के कामकाज पर जताई नाराजगी

सीएम ने लाड़ली लक्ष्मी के ड्रॉपआउट मामले में महिला और बाल विकास विभाग से नाराजगी जताई है। इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर समीक्षा करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे रोकने और ड्रॉपआउट पर सख्त निगरानी रखने का काम किया जाए। मुख्यमंत्री यादव ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री की टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए और कहा कि अगर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी होगी तो वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीएम को बताया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने में देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश बना है। बैठक में टेक होम राशन की प्रक्रिया में मध्यप्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। यह भी बताया गया कि स्पॉन्सरशिप योजना में 20,243 बच्चों को लाभ दिलाकर एमपी ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। झाबुआ के 'मोटी आई' नवाचार को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। बैठक में पीएम जनमन भवनों की डिजाइन और मॉनिटरिंग मॉड्यूल की भारत सरकार द्वारा विशेष सराहना किए जाने की जानकारी दी गई। एमपी में भवन निर्माण की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसमें 20 मीटर जियो-फेंसिंग आधारित उपस्थिति व्यवस्था है।

भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर हुई भोपाल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा

● मंत्री डॉ. शाह ने दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि ● राजधानी में लोगों ने मशाल लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की ● गैस पीड़ितों की रैली में आरएसएस की यूनीफार्म जैसा पुतला ● भाजपा नेता और गैस पीड़ितों में विवाद, पुलिस ने पुतला जब्त कर, रैली रोकी

भोपाल (नप्र)। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर भोपाल में बुधवार को गैस राहत मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह की उपस्थिति में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। विभिन्न धर्मगुरूओं ने धर्मग्रन्थों का पाठ किया और गैस त्रासदी को मानवता के लिए अपूरणीय क्षति बताया। मंत्री डॉ. शाह ने गैस त्रासदी में दिवंगत निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ऐसी त्रासदी भविष्य में कभी नहीं हो। श्रद्धांजलि सभा में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक श्री भगवान दास सबनानी, महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय, अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, कलेक्टर भोपाल श्री कौशलेंद्र सिंह, गणमान्य नागरिक और गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले संगठनो के प्रतिनिधि उपस्थित थे। धर्मगुरुओं में श्री रमेश त्रिपाठी, भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी, श्री गुरवेज सिंह, फादर अल्फ्रेड डी सूजा, श्री अजय जैन, शाक्य पुत्र सागर भंते ने अपने धर्म ग्रंथों का पाठ किया और दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी।

वहीं भोपाल में गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर बुधवार को निकली रैली अचानक बवाल में बदल गई। गैस पीड़ित संगठनों ने वारेन एंडरसन के पुतले के साथ आरएसएस जैसी यूनीफार्म वाला एक और पुतला लेकर मार्च शुरू किया। बीजेपी ने इसे आपत्तिजनक बताया और कुछ ही मिनटों में पुलिस ने विवादित पुतला जब्त कर रैली रोक दी।

रैली भारत टॉकीज अंडरब्रिज से जेपी नगर गैस त्रासदी स्मारक तक जाने वाली थी, लेकिन विवाद ने रास्ता बदल दिया। रैली गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही तनाव और आरोप-प्रत्यारोप ने माहौल गरमा दिया। संगठनों का दावा है कि यह पुतला आरएसएस का नहीं, बल्कि डाउ और यूनियन कार्बाइड के सहयोगियों का प्रतीक है। गैस पीड़ित संगठनों की रैली में ये दो पुतले हाथ ठेले पर रखे गए थे। इनमें से एक को आरएसएस की यूनीफार्म जैसे कपड़े पहनाए गए थे।

मुख्यमंत्री ने भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर दिवंगत पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 2 और 3 दिसम्बर 1984 की मध्य रात्रि में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं।

नोकझोंक हुई, पुलिस ने किया बीच-बचाव- गैस पीड़ित संगठन एक हाथठेले पर दो पुतले लेकर पहुंचे थे, जिसमें से एक पुतला आरएसएस की वेशभूषा की तरह कपड़े पहने था। सूचना मिलते ही बीजेपी मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आरएसएस वालों का पुतला जलाओगे? हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद बीजेपी और गैस पीड़ित संगठन के पदाधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा।

एसीपी बोले- एक पुतला हटा दिया गया- एसीपी राकेश सिंह बघेल ने कहा कि गैस पीड़ित एक्टिविस्ट रचना ढींगरा हर साल रैली निकालती हैं। भारत टॉकीज के पास लोग इकट्ठा हुए थे। एक ठेले पर दो पुतले थे। जब कपड़ा हटाया तो एक एंडरसन और दूसरा एक संगठन का पुतला निकला। इसे लेकर आपत्ति ली गई थी। इसके बाद पुतले को हटाया गया।

एसीपी बघेल ने बताया, तथ्यों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। यदि किसी संगठन को ठेस पहुंचाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विवाद के बाद रैली स्थगित कर दी गई।

भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर भाकपा का प्रदर्शन

यूनियन कार्बाइड से हुई गैस त्रासदी की 41 वीं बरसी पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 दिसम्बर 2025 को स्थानीय मंगलवारा चौराहे पर थाने के सामने गैस पीड़ितों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के अवसर पर गैस पीड़ितों की विभिन्न मांगों का ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति के लिए स्थानीय जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को सौंपा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद केन्द्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल के गैस पीड़ितों को अधिकतम मुआवजा नहीं देने पर सरकार की कड़ी भर्त्सना की है। इस अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने कहा कि हमारी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार केन्द्र और मध्य प्रदेश सरकार भोपाल के सभी गैस पीड़ितों को अधिकतम मुआवजा दे। गैस पीड़ितों और उनके परिवार जनों के आजीवन नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था हो। भोपाल मेमोरियल अस्पताल की स्वायत्तता कायम रहे। इसे कहीं भी मर्ज नहीं किया जाए इस अस्पताल में आधुनिकतम चिकित्सीय उपकरण, दवाई, पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था हो। स्टाफ की स्थाई नियुक्ति, उच्चतम वेतन और पेंशन सुनिश्चित हो सभी गैस पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों को 3000 की मासिक पेंशन मिले । भोपाल गैस त्रासदी का स्मारक, दस्तावेजों का संग्रहालय और शोध केन्द्र स्थापित किया जाए। एक राजनीतिक दल के रूप में सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही भोपाल के गैस पीड़ितों के हक और न्याय के लिए आवाज उठा रही है। भाकपा के लिए यह एक राजनीतिक संघर्ष भी है। एटक के प्रांतीय महासचिव कॉमरेड शिवशंकर मौर्य ने गैस पीड़ितों के हितों के लिए संवेदनहीनता पर भाजपा और कांग्रेस की भर्त्सना की और गैस पीड़ितों के लिए एकमात्र राजनीतिक दल भाकपा द्वारा किए गए विभिन्न आंदोलनों का उल्लेख करते हुए भाकपा के आंदोलनों के साथ एकजुटता की अपील की। इस तारतम्य में भाकपा के सदस्य कॉमरेड कल्लू खान ने भी संबोधित किया।

आंचलिक पत्रकारिता को सामाजिक संरक्षण की जरूरत

भोपाल । माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान परिसर में आंचलिक पत्रकारिता पर एक गंभीर विमर्श हुआ । इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार और बायोपिक फ़िल्म निर्माता राजेश बादल की पुस्तक गोलियों के सामने अडिग कलम का लोकार्पण हुआ। मुख्य अतिथि जाने माने संपादक और प्रेस कौंसिल के पूर्व सदस्य तथा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पूर्व महासचिव प्रकाश दुबे थे। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार एन के सिंह थे। अध्यक्षता संस्थान के संस्थापक संयोजक पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर थे।

इस कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए लेखक एवं नेशनल बुक ट्रस्ट के पूर्व संपादक पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह एक अनूठा मामला है,जिसमें पत्रकारों को सताने की न्यायिक जाँच कराई गई। पत्रकार इसमें जीते और प्रेस कौंसिल की जांच में भी पत्रकारों को सही ठहराया गया। इस अवसर पर छतरपुर से आए शुभ भारत के प्रधान संपादक श्याम अग्रवाल को पत्रकारिता में उनके 50 साल पूरे होने पर सम्मानित किया गया। श्री अग्रवाल ने पत्रकार उत्पीड़न मामले में सबसे अधिक उत्पीड़न झेला । श्याम जी ने अपने सम्मान के उत्तर में भावुक संबोधन दिया और कहा कि इस मामले के कारण उनके परिवार को चौदह साल तक इस मामले में मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ा है।

उनके अलावा छतरपुर से आए राष्ट्र भ्रमण के प्रधान संपादक सुरेन्द्र अग्रवाल, कृष्णक्रांति के प्रधान संपादक अजय दोसाज,वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला और सेवानिवृत आईएएस एल एस बघेल,जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त संचालक कबीर खान तथा एडवोकेट श्याम सुंदर श्रीवास्तव का भी सम्मान किया गया।

वरिष्ठ पत्रकार एन के सिंह ने कहा कि चार दशक बाद इस मामले की गूंज अभी तक सुनाई देती है और इस मामले ने साबित किया कि आंचलिक पत्रकारों की चुनौतियां और जोख़िम कम नहीं होते। श्री सिंह ने कहा कि राजेश बादल ने किस तरह इस घटना का दस्तावेजीकरण किया,वह सराहनीय है। श्री सिंह ने इस मामले पर अपनी तीखी टिप्पणियां लिखी थीं। मुख्य अतिथि प्रकाश दुबे ने कहा कि पत्रकारिता के ऐसे मामलों को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने उस ज़माने की प्रेस कौंसिल और वर्तमान प्रेस कौंसिल की तुलना करते हुए कहा कि वर्तमान प्रेस कौंसिल का गठन अरसे से लंबित है। पत्रकारिता के लिए ताकतवर मीडिया कौंसिल की सख़्त ज़रूरत है। पुस्तक के लेखक राजेश बादल ने कहा कि आमतौर पर किसी एक मामले की दो अर्ध न्यायिक जांच नहीं कराने की परंपरा है। लेकिन छतरपुर के मामले की एक साथ दो जांच हुईं। दोनों में पत्रकार जीते। उन्होंने कहा कि श्रीधर जी के कारण ही यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों की जीत के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने नई दुनिया के प्रधान संपादक स्वर्गीय राजेंद्र माथुर और रविवार के तत्कालीन संपादक स्वर्गीय एस पी सिंह के इस मामले में दिए गए सहयोग को याद किया ।इस मामले के एक और नायक स्वर्गीय शिव अनुराग पटेरिया को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी।

समारोह के अध्यक्ष पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर ने कहा कि छतरपुर के इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता की साख बढ़ाई है। मध्यप्रदेश आंचलिक पत्रकार संग ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और इसे अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सरोकारों की पत्रकारिता ही असली है ।यह मार्ग कठिन है,लेकिन सफलता का यही मुख्य मार्ग है। उन्होंने छतरपुर के सभी पत्रकारों की सराहना की और लगातार अपने सिद्धांतों पर टिके रहने के लिए बधाई दी।

सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र द्वारा जागरूकता कार्यक्रम

भोपाल। सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र संस्था द्वारा आंगनवाड़ी 710 और 1146 गोविंदपुरा में विश्व एड्स दिवस , भोपाल गैस त्रासदी और विश्वास दिव्यांगता दिवस पर मानसिक समस्याओं पर जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र की निदेशक स्मिता कुमारी ने एड्स से बचाव, भोपाल गैस त्रासदी के कारण हुई मानसिक एवं शारीरिक क्षति, दिव्यांगता से बचाव, दिव्यांगता के लक्षणों की शीघ्र पहचान, उपचार, एवं उनके पुनर्वास पर चर्चा की। साथ गर्भवती माताओं एवं प्रसूति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि 1 दिसम्बर को विश्व एड्स जागरूकता दिवस, 2-3 दिसम्बर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस और 3 दिसम्बर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। यह तीनों समस्याओं से मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभावत पड़ता हैं। इसलिए आज विश्व दिव्यांगता दिवस पर मानसिक समस्याओं से बचाव के लिए बताया कि किस प्रकार से मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कैसे समानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए, बचाव और चिकित्सकीय देखरेख के बाद भी अगर किसी कारण किसी बच्चे में असामान्य विकास दिखे तो तत्काल थेरेपी से काफी हद तक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है उन बच्चों के दिव्यांगता का शीघ्र पहचान कर उनकी क्षमताओं का बेहतर विकास करना। उन्होंने आगे बताया कि इसमें थेरेपिस्ट, अभिभावक, रिश्तेदार, आसपड़ोस, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया, शासन-प्रशासन सबकी साझी जिम्मेदारी है कि इस विषय पर खुलकर बात करें, लोगों के बीच अनुभव साझा करें जिससे दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना सहज और सरल हो। स्मिता ने आगे यह भी बताया कि दिसम्बर माह में ही सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र का 11वाँ स्थापना दिवस भी हैं। इस उपलक्ष्य पर यह तय किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए महीने में कम से कम एक दिन शासकीय संस्थानों के हितग्राहियों को केंद्र द्वारा निःशुल्क सेवा दिया जायेगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूक किया जा सकें। इस केंद्र के माध्यम से पिछले 11 सालों से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता, शोध कार्य, इंटर्नशिप और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, कार्यक्रम में आये दिव्यांगजन और अवसाद ग्रस्त महिला का स्क्रीनिंग करके चिकित्सा सुविधा की जानकारी दी। जरूरत अनुसार थेरेपी बताई, दिव्यांग प्रमाणपत्र एवं शासन की सुविधाओं की जानकारी दी. साथ ही कार्यक्रम में सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र से निदेशक स्मिता कुमारी, सुमित कुमार, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता मधु सोनी, सहायिका मंजू तिवारी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से दो इंटर्न कोंपल राखोंडे एवं अभिनव शर्मा भी शामिल हुए।

एक नंबर की दो कार जब्त

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रातीबड़ इलाके से दोनों कार जब्त की, जांच शुरू

भोपाल (नप्र)। भोपाल के रातीबड़ इलाके में बुधवार को एक ही नंबर की दो गाड़ियां मिली हैं। पुलिस ने दोनों कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। टीआई रासबिहारी शर्मा के मुताबिक सूचना मिली थी कि गोल्डन सिटी कॉलोनी नीलबढ़ में दो गाड़ियां खड़ी हैं। दोनों कार का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक गाड़ी पोलो है, जिसका नंबर एमपी 09 सीएच 5447 है, जबकि दूसरी कार फोर्ड कंपनी की है, जिसका नंबर भी वही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि दोनों गाड़ियां लावारिस हालत में सुबह से खड़ी थीं। जिसके मालिकों को भी कोई पता नहीं है, क्योंकि आसपास के लोगों से पूछताछ कर ली है। चूंकि मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने दोनों को जब्त कर लिया है। आरटीओ की वेबसाइट पर देखा तो पाया कि गाड़ी का नंबर फोर्ड की कार का है। जिससे पता चलता है कि पोलो कार पर लिखा हुआ नंबर फर्जी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। जिससे कार को छोड़ने वाले की पहचान की जा सके।

आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे भाजपा विधायक

● उमाकांत शर्मा बोले- सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो केस लगाऊंगा, ब्राह्मण बेटियों पर की थी टिप्पणी

भोपाल (नप्र)। एमपी के प्रमोटी आईएएस और अजाक्स के प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी-कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को ब्राह्मण नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग की। अब सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने संतोष वर्मा के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। शर्मा ने कहा- मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आहत हूं। बेटी संसार में किसी की भी हो, बेटी वंदनीय, पूजनीय है। बता दें कि अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में सीनियर आईएएस अधिकारी और नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा ने कहा था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए।

- **शर्मा बोले- बेटी का अपमान सार्वजनिक अपराध-** विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ ये हमारा लक्ष्य है। किसी भी बेटी का अपमान करना, अनैतिक अभद्र, अपमानजनक, जाति-समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करना ये सार्वजनिक अपराध है। इसके खिलाफ जल्द से जल्द हमारी सरकार और केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय कार्रवाई करेगा। ऐसा मुझे विश्वास है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में जाकर इस्तगासा (निजी परिवाद) पेश करूंगा।
- **कांग्रेस-भाजपा दोनों ने वर्मा के निलंबन की मांग की-** आईएएस संतोष वर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। इसी मुद्दे पर मंगलवार को कांग्रेस और भाजपा, दोनों दलों के विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिला और संतोष वर्मा को तत्काल निलंबन करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।